CNews सिटी चीफ

सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-339
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

अपने रास्ते खुद चुनिए
क्योकि आपको आपसे बेहतर कोई
नहीं जानता

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, रविवार 16 मार्च 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

होली पर सीएम मोहन यादव का तोहफा

एमपी के पुलिसकर्मियों को मिलेगा अब अपना घर

उज्जैन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने होली के अवसर पर पुलिसकर्मियों को बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस जवानों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, ताकि वे अपने घर का सपना साकार कर सकें। सीएम मोहन यादव उज्जैन में पुलिस होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस विभाग में भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को जल्द ही सुचारु करने की बात भी कही।

पुलिसकर्मियों के लिए सरल होगी आवास निर्माण प्रक्रिया उज्जैन पुलिस लाइन में आयोजित होली मिलन समारोह में सीएम मोहन यादव ने पुलिसकर्मियों के साथ होली खेली और उन पर पुष्पवर्षा कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पुलिस जवान समाज की सेवा में दिन-रात तत्पर रहते हैं, लेकिन अगर उनका खुद का घर नहीं होगा, तो वे पूरे मन से कैसे काम कर पाएंगे? इसलिए, सरकार उनकी आवास निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने जा रही है। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की निष्ठा और समर्पण की जमकर तारीफ भी की।

पुलिस विभाग में 8500 से अधिक नई भर्तियां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समारोह में घोषणा की कि पुलिस विभाग में 8500 से अधिक नई भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक 6600 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती कर चुकी है और जल्द ही 8500 से अधिक पुलिस कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर की भर्तियां भी निकाली जाएंगी।

वॉशिंगटन के गड्ढों और गंदगी से परेशान ट्रंप

राष्ट्रपति बोले- मैं नहीं चाहता था कि मोदी तंबू देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने बदलवा दिया था प्रधानमंत्री का रास्ता

न्यूयॉर्क। वैश्विक राजनीति में अपने बयानों और फैसलों से उथल-पुथल मचाने वाले ट्रंप अपनी राजधानी में फैली गंदगी से परेशान चल रहे हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि पिछले एक महीने में पीएम मोदी, पीएम स्टार्मर, राष्ट्रपति मैक्रों समेत कई वैश्विक नेता उनसे मिलने के लिए वॉशिंगटन आए थे और वह नहीं चाहते थे कि यह वैश्विक नेता वाशिंगटन में सरकारी भवनों के आसपास लगे तंबू या दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को देखें। ट्रंप ने कहा कि इसलिए मैंने व्हाइट हाउस आने के उनके रास्ते को बदलवा दिया था। इसके साथ ही मैंने शहर को साफ करने का आदेश भी दिया था।

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट में भाषण देते हुए ट्रंप ने कहा, हम अपने शहर की सफाई कर रहे हैं। हम अपनी राजधानी की सफाई कर रहे हैं और हम यहां और अपराध नहीं होने देंगे, हम किसी भी हाल में अपराध के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। हम शहर की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स या ग्रेफिट्स को हटाने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने टेंट्स को हटाने से कर दी है। प्रशासन अपना काम बेहतर ढंग से कर रहा है और हम उनके साथ हैं।

हम एक ऐसी राजधानी चाहते हैं जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन के मेयर म्यूरियल बोसर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राजधानी की सफाई की दिशा में बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रायल के ठीक सामने बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं। हमें उन्हें हटाना होगा.. हम एक ऐसी राजधानी चाहते हैं जो दुनियाभर में चर्चा का विषय बन सके।

मैंने बदलवा दिया था रास्ता ताकि गड्ढे न देख सकें ट्रंप ने कहा,जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति ये सभी लोग... ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सभी पिछले डेढ़ सप्ताह में मुझसे मिलने आए थे और जब वे आए... तो मैंने उनका रास्ता बदलवाया था। मैं नहीं चाहता था कि वे तंबू लगे देखें। मैं नहीं चाहता था कि वे दीवारों पर की गई कलाकारी को देखें। मैं नहीं चाहता था कि वे सड़कों पर टूटे हुए बैरियर और गड्ढे देखें। हमने इसे सुंदर बना दिया।'

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने बीती 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। जनवरी में ट्रंप के शपथ ग्रहण के कुछ ही हफ्तों में ही कई वैश्विक नेता अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इनमें पीएम मोदी के अलावा इस्त्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आदि नेता शामिल हैं।

केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

50 साल की महिला को सरोगेसी से मातृत्व का अधिकार

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने शादीशुदा महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 50 साल की महिला को सरोगेसी के जरिए मां बनने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश नितिन जमदार और जस्टिस एस. मनु की डिवीजन बेंच ने पहले के फैसले को पलटते हुए कहा कि मातृत्व जीवन का मौलिक पहलू है और इसे कानून के तहत सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में शादीशुदा महिलाओं के लिए सरोगेसी की उम्र सीमा 23 से 50 साल के बीच निर्धारित की गई है, और याचिकाकर्ता इस दायरे में आती हैं। इससे पहले, केरल स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड (KSARTSB) ने महिला को

सरोगेसी की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी कानून का उद्देश्य अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाना है, न कि सही मामलों में महिलाओं को मातृत्व के अधिकार से वंचित करना। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता के पास मां बनने का आखिरी अवसर है और इस अधिकार से उसे वंचित करना उचित नहीं होगा।

एक हफ्ते में मिलेगा प्रमाणपत्र डिवीजन बेंच ने KSARTSB को आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर महिला को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाए। यह फैसला महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना का अहम बयान

कानून के क्षेत्र में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जरूरी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने शनिवार को महिलाओं के लिए आरक्षण की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अच्छा कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों में कम से कम 30 प्रतिशत विधि अधिकारी महिलाएं होनी चाहिए। बता दें कि न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह बात मुंबई विश्वविद्यालय में आयोजित %ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग %वूमेन हू मेड इट% सेमिनार में कही। अपने संबोधन में न्यायाधीश न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उच्च न्यायालयों में महिलाओं की नियुक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए,

क्योंकि यदि 45 वर्ष से कम आयु के पुरुष अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया जा सकता है, तो सक्षम महिला अधिवक्ताओं को क्यों नहीं?

महिलाओं को अपने सपनों का पालन करना चाहिए साथ ही न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा कि महिलाओं को लिंग-आधारित भेदभाव से मुक्त होकर अपने सपनों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी मेहनत और नेतृत्व के जरिए सफलता पा सकती हैं, जैसा कि कई महिलाएं कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि घर की देखभाल करने वाली महिलाएं, जो समाज में अधिकतर अनदेखी होती हैं, उनका योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भारतीय पंचायतों में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सकारात्मक उदाहरण बताया, जहां महिलाएं आरक्षण के माध्यम से नीति निर्माण में शामिल हो रही हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है।

सोना तस्करी मामला

एक्ट्रेस रान्या राव के सौतेले पिता डीजीपी रामचंद्र राव पर कार्रवाई

नई दिल्ली। सोने की तस्करी मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव के सौतेले पिता डीजीपी रामचंद्र राव पर भी कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उन्हें अनिवार्य छुट्टी पर भेज दिया गया। आईपीएस ऑफिसर राव फिलहाल कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। दुबई से आने पर 3 मार्च को केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की सोने की बिस्किट जब्त की गई थी। इसके बाद उनके आवास की तलाशी ली गई। अधिकारियों ने कहा कि 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए गए। डीआरआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई भी मामले की एक साथ जांच कर रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने अदालत में कहा कि कर्नाटक पुलिस प्रोटोकॉल अधिकारी का इस्तेमाल रान्या राव से जुड़े सोना तस्करी गिरोह में किया गया था। रान्या को जमानत देने के खिलाफ अपनी दलील में केंद्रीय एजेंसी ने आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत को बताया कि आरोपी ने इस साल जनवरी से 27 बार दुबई की यात्रा की थी। डीआरआई ने कहा, अब तक की जांच में सोने की तस्करी में इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली, सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए राज्य पुलिस प्रोटोकॉल अधिकारी का इस्तेमाल, सोना खरीदने के लिए भारत से दुबई में धन स्थानांतरित करने के लिए हवाला लेनदेन और बड़े गिरोह की संलिप्तता का पता चला है। इन दलीलों के बाद अदालत ने शुक्रवार को रान्या को जमानत देने से इनकार कर दिया। डीआरआई पर मारपीट, जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप इस बीच, रान्या राव ने राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ मारपीट की गई और उसे खाली व पहले से लिखे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। रान्या ने बेंगलुरु में डीआरआई के अतिरिक्त महानिदेशक को संबोधित 6 मार्च को लिखे पत्र में दावा किया कि उन पर झूठा मामला थोपा गया है।

इंडसइंड बैंक के पास पर्याप्त पूंजी

जमाकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। इंडसइंड बैंक में चल रहे संकट के बीच देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि इंडसइंड बैंक वित्तीय रूप से स्थिर है और बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, इसलिए जमाकर्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक के बयान में बताया गया कि बैंक के वित्तीय नतीजों की ऑडिटर द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें पता चला है कि 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुई तिमाही में

बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है और इसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.46 प्रतिशत है, वहीं प्रावधान कवरेज अनुपात 70.20 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक के अनुसार, इंडसइंड बैंक का 9 मार्च 2025 तक लिक्विडिटी कवरेज अनुपात 113 प्रतिशत है, जबकि विनियामक नियमों के तहत ये 100 प्रतिशत होना चाहिए। इंडसइंड बैंक के शेयर मंगलवार को 27.06त्न गिरकर 656.80 रुपये पर गिरकर बंद हुए। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में गड़बड़ी बताई जा रही है। इससे बैंक का मार्केट कैप 2.35 प्रतिशत कम हो गया। बैंक पर निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा तो लोगों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे बैंक के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई।

बलूच विद्रोहियों ने कहा, हमने सभी 214 बंधकों को मार डाला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने सभी 214 बंधकों को मार डाला है। बीएलए के विद्रोहियों ने बताया कि जिन 214 लोगों को मारा गया है वे सभी पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। पाक सेना की हार करार देते हुए बीएलए के प्रवक्ता ने कहा कि इन मौतों के लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं थी। इन मौतों के बाद भी पाक सरकार कोई संवाद नहीं कर रही है। बता दें कि मंगलवार को बलोच विद्रोहियं ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बोलन दर्रे के पास हाइजैक कर लिया था। इस ट्रेन में कम से कम 450 लोग सवार थे। इसके बाद सेना बचाव करने पहुंची तो बलोच विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कम से कम दो दर्जन जवान मारे गए थे। वहीं 33 बीएलए लड़ाकों को भी मारने का दावा किया गया था।

इसरो की बड़ी सफलता : क्रायोजेनिक इंजन की हॉट टेस्टिंग सफल, एलवीएम-3 में होगा इस्तेमाल

बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने क्रायोजेनिक इंजन के गर्म परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह इंजन इसरो के लॉन्च वाहन मार्क-3 (एलवीएम-3) में लगाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परीक्षण को तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रणोदन परिसर में अंजाम दिया गया।

क्रायोजेनिक इंजन का गर्म परीक्षण क्यों जरूरी? इसरो ने अपने बयान में कहा कि हर अंतरिक्ष मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का गर्म परीक्षण आवश्यक होता है। इस बार इंजन को 100 सेकंड तक निर्वात रहित स्थिति में नोजल सुरक्षा प्रणाली के साथ परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान के दौरान आवश्यक तैयारी समय में कमी आएगी, जिससे अंतरिक्ष अभियानों के लिए क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से आपूर्ति संभव होगी।

एलवीएम-3- इसरो का नया भारी उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो के अनुसार, क्रायोजेनिक इंजन ने सभी परीक्षण उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इसे एलवीएम-3 के ऊपरी चरण में लगाया जाएगा। एलवीएम-3 को इस साल के मध्य में प्रक्षेपित करने की योजना है।

एलवीएम-3 इसरो का नया तीन-स्तरीय भारी उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसमें—

एस200 ठोस ईंधन सहायक रॉकेट बूस्टर
एल110 द्रव इंजन चरण

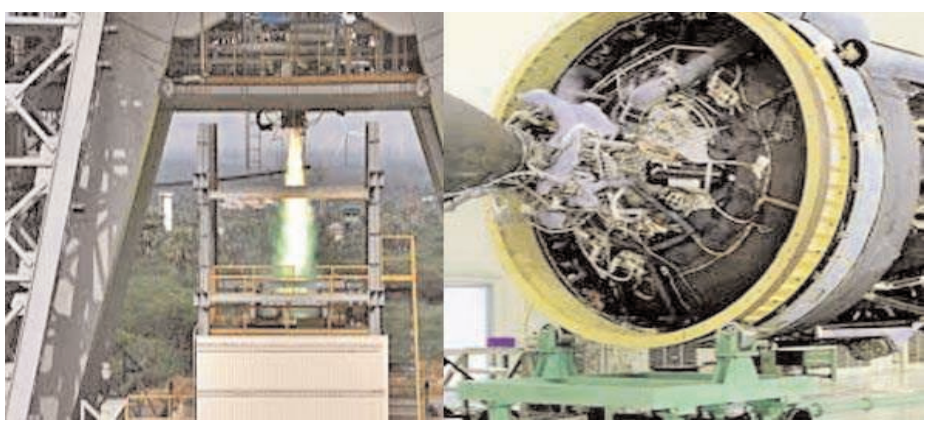

सी25 क्रायोजेनिक चरण उपकरण खंड (ईबी) और संलग्न संयोजन (ईए) शामिल हैं।

इंदौर की ऐतिहासिक गेर देखने के लिए ऑनलाइन बुक कर सकेंगे सीट

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर में परंपरागत रूप से निकलने वाली रंगारंग गेर को देखने के लिए शहर के अलावा अन्य शहरों और विदेश से भी लोग पहुंचने लगे हैं। पिछले साल की तरह ही इस बार भी लोगों की सुविधा के लिए गेर मार्ग के घरों की छतों पर गेर देखने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। करीब आठ घरों की छतों पर 100 लोगों की बैठक व्यवस्था तय की गई है। इसके लिए बुक माय शो पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सोमवार से बुकिंग शुरू हो जाएगी। रंगपंचमी पर शहर के मध्य क्षेत्र राजवाड़ा में निकलने वाली ऐतिहासिक गेर में लाखों लोग शामिल होते हैं। इस गेर में कई मीटर ऊंचाई तक रंग-गुलाल उड़ाया जाता है।

आठ घरों को चिह्नित किया गया है

इस गेर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी संस्कृति विभाग द्वारा भेजा गया है। अन्य शहरों से आने वाले लोग परिवार के साथ गेर का आनंद ले सकें, इसके लिए घरों की छतों पर बैठक व्यवस्था की जा रही है। अभी आठ घरों को चिह्नित किया जा चुका है।

स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांक सिंह का कहना है कि रविवार को

रहवासियों के साथ बैठक की जाएगी। इसमें अन्य घरों पर बैठक व्यवस्था करने को लेकर चर्चा होगी। इसमें मकान की मजबूती और छत पर बैठक व्यवस्था का आकलन किया जाएगा। परिवार के अतिरिक्त कितने लोगों को बैठाया जा सकेगा, यह भी रहवासियों से चर्चा कर तय किया जाएगा।

घरों तक पहुंचाएंगे वालंटियर

घरों की छतों पर गेर देखने के लिए बुकिंग करवाने वाले लोगों की सुविधा के लिए 20 से 25 वालंटियर तैनात किए जाएंगे। यह वालंटियर लोगों को छतों तक पहुंचाने के अलावा वापस छोड़ने का काम संभालेंगे। इससे लोगों को तय छतों तक पहुंचने में सुविधा होगी। यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां, पेयजल और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी।

न्यूनतम शुल्क चुकाकर देख सकेंगे गेर

गेर मार्ग के घरों की छतों पर बैठकर रंगों का आनंद लेने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन 200 से 250 लोगों की बैठक व्यवस्था करने में जुटा है। हालांकि छत पर बैठकर गेर देखने के लिए कितना शुल्क चुकाना होगा, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि न्यूनतम शुल्क चुकाकर यह सुविधा लोगों को मिल सकेगी और मकान मालिक को कुछ किराया मिल सकेगा।

गेर का आनंद घरों की छतों पर बैठकर लेने की शुरुआत बीते साल हुई थी। इसमें विदेशियों के अलावा अन्य शहरों के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। करीब 200 लोगों की व्यवस्था प्रशासन द्वारा बगैर शुल्क लिए की गई थी। अधिकारियों को बुकिंग के लिए नियुक्त किया गया था। अब इस व्यवस्था को ऑनलाइन बनाया जा रहा है। वहीं घरों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गेर मार्ग पर तैनात होगी एंबुलेंस

कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि गेर के दौरान मार्ग पर एंबुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। चार से पांच एंबुलेंस रहेंगी और उनकी निकासी के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। मार्ग में विद्युत तारों को ऊंचा किया जाएगा और डीपी को कवर किया जाएगा। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था भी रहेगी।

इंदौर में वकीलों का हंगामा, टीआई पर भड़के, पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर में हाईकोर्ट चौराहे पर शनिवार को वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। तीन घंटे तक चले इस हंगामे के दौरान वकीलों और टीआई के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद टीआई को खुद को बचाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। वकीलों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अंततः अधिकारियों ने पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन वकील इससे संतुष्ट नहीं हुए और सोमवार तक एफआईआर दर्ज न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

होली के रंग से शुरू हुआ विवाद पुलिस-प्रदर्शन तक पहुंचा

घटना की शुरुआत होली के दिन हुई, जब कुलकर्णी का भट्टा निवासी राजू उर्फ कालू गौड़ (50) मंदिर जा रहे थे। रास्ते में दो बच्चों ने उन पर रंग डाल दिया। इस पर राजू ने बच्चों को रोकने की कोशिश की। तभी अरविंद जैन नामक व्यक्ति वहां पहुंचे और कहासुनी करने लगे। देखते ही देखते विवाद बढ़ा और अरविंद के दोनों बेटे, वकील अपूर्व और अर्पित जैन भी वहां आ गए। उन्होंने राजू से मारपीट शुरू कर दी।

विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कुछ वकील भी पुलिस की लाठी का शिकार हो गए। इसी के विरोध में शनिवार को वकीलों ने हाईकोर्ट चौराहे पर चक्काजाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ

सख्त कार्रवाई की मांग की।

वकीलों ने किया विरोध, सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा

वकील पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे और लगातार दोषी पुलिसकर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान वकील सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस बीच, वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई।

प्रदर्शन के बाद पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड, टीआई की जांच की मांग

वकीलों के उग्र विरोध के बाद एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। हालांकि, वकील इससे संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि टीआई जितेंद्र सिंह यादव भी घटना के दौरान नशे में थे और उनकी मेडिकल जांच कराई जानी चाहिए। वकीलों ने सोमवार तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेंगे और जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन करेंगे। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी।

इंदौर में इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण छह माह लेट, पिछले साल अगस्त में आई थी टीम

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। सात बार से लगातार सबसे साफ शहर का ताज बरकरार रखने वाले इंदौर को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण टीम लंबा इंतजार करवा रही है। चार माह से इंदौर में सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी तक दिल्ली से टीम नहीं आई। इस बार सर्वेक्षण छह माह लेट हो गया है। पिछले साल अगस्त माह में इंदौर में सर्वे हो चुका था और जनवरी माह में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग भी घोषित हो चुकी थी, लेकिन इस बार अभी तक सर्वेक्षण ही नहीं हो पाया है। देश के दूसरे शहरों में आनलाइन फीडबैक शुरू हो चुका है, लेकिन टीम किसी भी शहर में अब तक नहीं जा पाई है। पहले 15 मार्च तक सर्वेक्षण टीम आने के संकेत मिले थे, लेकिन अब मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंदौर में सर्वेक्षण हो सकता है। वैसे भी इस बार इंदौर को प्रीमियर लीग में रखा गया है। यहां इंदौर का मुकाबला सूरत और नवी मुंबई से है। पिछले तीन वर्षों से कम से कम दो वर्षों में टॉप थ्री में आने वाले शहरों को इसमे जगह मिली है। इंदौर सात बार से पहले स्थान पर है, इसलिए इंदौर को सबसे पहले शामिल किया गया। इंदौर के अलावा 11 अन्य शहर भी स्वच्छता सुपर लीग में स्थान पा चुके है।

मेयर पुष्य मित्र भार्गव को इस बार भी स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने का पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि स्वच्छता का जनभागीदारी मॉडल इंदौर में सबसे मजबूत है। हमारी ताकत लोगों की जनभागीदारी है। लोग कचरा घरों और संस्थानों में संभालकर रखते है। उन्हें खुले में नहीं फेंकते।

सुबह आने वाले कचरा वाहनों में ही उसे डाला जाता है। इस कारण सड़कें व परिसर लंबे समय तक साफ रहते है। शहर जीरो डस्टबीन सिटी है। इस कारण कचरा खुले में नजर नहीं आता। देश के दूसरे शहरों में कचरे के ढेर कई जगह नजर आते है। इस बार शहर को सुंदर बनाने पर भी जोर दिया है। वॉल पेंटिंगों के अलावा शहर के उद्यानों में कचरे से सुंदर कलाकृतियां बनाई गई है।

सांसों में तकलीफ, बुखार फिर निमोनिया, इंदौर में बढ़ रहे खतरनाक बुखार के मरीज

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। शहर में इन दिनों लोग खतरनाक वायरल की चपेट में आ रहे है। एन्फ्लूएंजा-ए और एच-3, एन-2 से मिलते जुलते इस वायरल के लक्षण बुखार, सांसों में तकलीफ है। कई बार इससे निमोनिया भी मरीजों को हो रहा है और उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ रहा है। हर दिन अस्पतालों में 50 से 70 मरीज इस वायरल के इलाज के लिए आ रहे है। शहर के छाती रोग विशेषज्ञ रवि डोसी इस वायरल के खतरनाक होने की वजह मौसम का उतार-चढ़ाव बता रहे है। पहले गर्मी आई, फिर अचानक सर्दी बढ़ गई। इस तरह का मौसम वायरल के फैलाव के लिए अनुकूल होता है। इन दिनों लोग धार्मिक स्थलों पर भी काफी जाते है। कई मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री मिली है। पर्यटन के दौरान वे वायरल के चपेट में आ रहे है और

फिर उनके संपर्क में आने के कारण दूसरे लोग व परिवारजन भी चपेट में आ रहे है।

इम्यूनिटी कमजोर तो जानलेवा बन सकता है बुखार

शहर में फैले वायरल की चपेट में आने वाले जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए यह बुखार जानलेवा साबित हो रहा है। सांसों में तकलीफ और निमोनिया के कारण कुछ मरीजों को आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ रहा है। बच्चों और युवकों पर इस वायरल का ज्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है। डा. डोसी के अनुसार इस मौसम में यह वायरल तेजी से फैलता है। रोगी के संपर्क में आने यह फैलता है। सामान्य तौर पर कुछ लोगों को सिर्फ बुखार आता है, लेकिन कुछ मरीजों में

सोना 90 हजार और चांदी 1 लाख के पार इंदौर सराफा बाजार में नए रिकॉर्ड

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया। शनिवार को चांदी के दाम पहली बार 1 लाख 1 हजार 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए, जबकि सोने ने 90 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छू लिया। यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मजबूती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण देखने को मिली।

विशेषज्ञों के अनुसार, डॉलर इंडेक्स में गिरावट और अमेरिका

में संभावित महंगाई बढ़ने की आशंका के चलते सोने-चांदी की मांग बढ़ रही है। फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में इन धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं।

इंदौर के बंद भाव

सोना- कैडबरी रवा नकद 88,900 रुपये, आरटीजीएस 90,000 रुपये, 22 कैरेट 82,500 रुपये प्रति 10 ग्राम चांदी- चौरसा 99,200 रुपये, आरटीजीएस 1,01,500 रुपये, टंच 99,400 रुपये प्रति किलो, चांदी सिक्का 1,085 रुपये प्रति नग इससे पहले गुरुवार को सोना 88,100 रुपये और चांदी 98,400 रुपये पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना 2,983 डॉलर और चांदी 3,379 सेंट प्रति औंस तक पहुंच चुकी है।

होली के बहाने चहरे पर गोबर मसला, तीन के खिलाफ एफआईआर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। राजनगर में शुक्रवार को होली की आड़ में मनचलों ने हुड़दंग किया।लोगों को परेशान किया और रंग की जगह गोबार लगा दिया।पुलिस ने तीन के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। घटना चंदननगर थाना अंतर्गत सांवरिया टैंट हाऊस के समीप की है।पुलिस ने रामानंदनगर निवासी पवन सुंदरलाल राणा की शिकायत पर आरोपित संजय,ऋतिक और पीयूष के खिलाफ केस दर्ज किया है। पवन के मुताबिक वह राजनगर से निकल रहा था।कालोनी में रहने वाले युवक होली खेल रहे थे।आरोपितों ने जबरदस्ती बाइक रोकी और मुंह पर गोबर लगा दिया।पवन ने उन्हें समझाया तो विवाद करने लगे। आरोपितों ने गालियां दी और डंडे से पिटाई कर दी।पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। उधर, संयोगितागंज पुलिस ने न्यू आरटीओ रोड़ निवासी केशव गोयल की शिकायत पर तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।केशव के मुताबिक पानी की गुब्बारा मारने से मना करने पर आरोपितों ने झगड़ा किया और धारदार हथियार से हमला कर दिया। उधर एरोड्रम थाना क्षेत्र में भी होली पर विवाद हो गया।कृष्ण विहार कालोनी निवासी गोलू गुप्ता ने बाइक सवार युवकों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है।फरियादी ने पुलिस को बताया कि वह सरोज वाटिका के समीप होली खेल रहा था। बाइक सवारों ने गाली दी और कहा कि पानी का गुब्बारा मत फैंकना।इस बात पर झगड़ा किया और चाकू मार दिया।

साईं महोत्सव में निकली पालकी यात्रा, सिंधी कॉलोनी में श्रद्धालुओं ने किया स्वागत

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। श्री साईं बाबा महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय साईं सेवा समिति के तत्वाधान में भव्य पालकी यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा 13 मार्च से शुरू हुई है जो कि 5 अप्रैल तक प्रतिदिन अलग-अलग स्थानों से निकलेगी। 15 मार्च को पालकी यात्रा ओटवानी और मोरवानी परिवार द्वारा आयोजित की गई।

जगदीश मोरवानी ने बताया कि परंपरा के अनुसार सबसे पहले साईं बाबा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद आरती के साथ पालकी यात्रा की शुरुआत हुई। प्रभातफेरी के मार्ग में रंगोली सजाई गई। सिंधी कॉलोनी के निवासियों ने अपने घरों के बाहर दीप जलाकर और रंगोली बनाकर पालकी का स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर साईं बाबा का पूजन-अर्चन किया। हरीश ओटवानी ने बताया कि यह आयोजन पिछले 15 वर्षों से लगातार हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से %स्वच्छ इंदौर, सुंदर इंदौर% और %जल ही जीवन है% का संदेश भी दिया जा रहा है। सिंधी कॉलोनी में विभिन्न स्थानों पर मंच बनाकर पालकी का भव्य स्वागत किया गया।

खजराना गणेश मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा, विदेशी मुद्रा और आभूषण मिले

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में भक्तों द्वारा अर्पित दान की गणना जारी है। अब तक की गिनती में मंदिर को 1.21 करोड़ रुपये नकद प्राप्त हुए हैं, जबकि बड़ी मात्रा में आभूषण भी चढ़ावे में मिले हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार दानपेटियों में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट भी मिले हैं, जिनकी कुल कीमत 9,500 रुपये है। ये नोट 2016 की नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हो चुके हैं।

6 मार्च से जारी है गिनती मंदिर समिति द्वारा 6 मार्च से शुरू की गई इस गणना प्रक्रिया में 15 सदस्यीय टीम कार्यरत है। नकदी को मशीनों के माध्यम से गिना जा रहा है और सौ-सौ नोटों की गड्डियां बनाकर बैंक में जमा किया जाएगा। समिति का कहना है कि दान में प्राप्त राशि और आभूषणों का उपयोग मंदिर की व्यवस्थाओं और सेवाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की मनोकामना से जुड़ी चिट्ठियां दानपेटियों में मिली हैं।

इस बार दानपेटियों से विदेशी मुद्रा, आभूषणों के अलावा कुछ रोचक चीजें

भी सामने आई हैं। किसी श्रद्धालु ने महंगी लेडीज वॉच चढ़ावे में अर्पित की है, जबकि कई भक्तों द्वारा लिखी गई मनोकामना की चिट्ठियां भी मिली हैं। दान में डॉलर और दिरहम जैसी विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनकी गणना अभी जारी है।

पिछली बार 1.75 करोड़ का चढ़ावा मिला था

मंदिर समिति के असिस्टेंट मैनेजर गौरी शंकर मिश्रा के अनुसार, पिछली बार तीन महीनों में मंदिर को 1.75 करोड़ रुपये की दान राशि प्राप्त हुई थी। इस बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के चलते दानपेटियां अपेक्षाकृत जल्दी खोली गईं, और सवा दो माह में ही 1.21 करोड़ रुपये की राशि गिनी जा चुकी है। यह पहली बार नहीं है जब मंदिर में बंद हो चुके नोट चढ़ाए गए हों। दो साल पहले भक्तों ने 2 लाख रुपये के 2,000 रुपये के नोट दान किए थे, जबकि पिछले वर्ष सितंबर में 1.58 लाख रुपये मूल्य के ऐसे ही नोट चढ़ावे में मिले थे। दानपेटियों से प्राप्त राशि और आभूषणों का उपयोग मंदिर के विकास कार्यों और भक्तों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधि की सूचना देने वालों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ेगी।

नक्सलवाद को खत्म करने एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ मिलकर चलाएंगे ऑपरेशन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस मिलकर रणनीति बनाएगी। तीनों राज्यों की पुलिस आपसी सहयोग से नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करेगी और खुफिया जानकारियां साझा करेगी। मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाई जाएगी।

नक्सली गतिविधियों पर कड़ी नजर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशानुसार अगले वर्ष तक नक्सलवाद के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है। नक्सली तीनों राज्यों को मिलाकर अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, इसलिए इन राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय से कार्रवाई करेगी। नक्सल विरोधी ऑपरेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाएगा और मध्य प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी।

मध्य प्रदेश में 70 नक्सली सक्रिय

मध्य प्रदेश में सक्रिय करीब 70 नक्सलियों में से केवल तीन ही राज्य के मूल निवासी हैं, जबकि बाकी नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इन नक्सलियों को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ही प्रशिक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में चल रहे लगातार अभियानों के कारण वहां से भागकर नक्सलियों के मध्य प्रदेश में छुपने की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को अधिक सतर्क किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार की नई रणनीति

खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता लेकर नक्सल विरोधी ऑपरेशन को तेज किया जाएगा।

नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर और सरकारी योजनाओं के लाभ देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों के जरिए अन्य नक्सलियों को समर्पण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

जब्त नक्सली साहित्य और सामग्री की जानकारी आपस में साझा की जाएगी, जिससे सुरक्षा बलों की तैयारी मजबूत हो सके।

नक्सली मुठभेड़ों के बाद तीनों राज्यों की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई जाएगी।

जोनल कमेटी के गिरफ्तार पदाधिकारियों से पूछताछ के लिए संबंधित राज्यों में जाकर जांच की जा सकेगी।

मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सहयोग से इस अभियान को प्रभावी बनाने में जुटी हुई है। सरकार का लक्ष्य है कि नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त कर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।

मार्च में 4 दिन लू का अलर्ट, ज्यादा तपेंगे इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। मध्य प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है मार्च महीने में ही 40 के करीब तापमान दर्ज किया जा रहा है। होली के दिन प्रदेश के नर्मदापुरम का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च के आखिरी 15 दिनों में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ेगी। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है। 4 दिन तक लू चलने का भी अलर्ट है। वहीं, अप्रैल-मई में 20 दिन हीट वेव चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-चंबल सबसे ज्यादा तपेगा।

तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना

मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह का कहना है कि मार्च में बारिश के सामान्य से कम होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, तापमान के सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। प्रदेश में मार्च से ही हीट वेव यानी लू भी चलेगी। 15 मार्च के बाद जब शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंचेगा, तब गर्म हवा का असर देखने को मिलेगा। हालांकि, इससे पहले ही खजुराहो, नर्मदापुरम, रतलाम, मंडला समेत कई शहरों में पारा 39 डिग्री के पार पहुंच गया।

जानें कब होता है हीट वेव का असर

मौसम विभाग के अनुसार सामान्यत: दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक या सामान्य से 4.6 डिग्री तक हो तो हीट वेव यानी लू की स्थिति मानी जाती है। चूंकि, प्रदेश में अभी पारा 39 डिग्री तक आ चुका है। कई शहरों में तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अगले सप्ताह में प्रदेश में लू चलने लगेगी। मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो जाती है। अगले 4 महीने तेज गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने मार्च से मई तक 15 से 20 दिन तक हीट वेव चलने का अनुमान जताया है। अप्रैल-मई में हीट वेव का असर ज्यादा हो सकता है। इस कारण 30 से 35 दिन तक गर्म हवा चल सकती है।

ऐसा रहेगा मार्च का दूसरा पखवाड़ा

15 मार्च के बाद न्यूनतम तापमान इंदौर संभाग में सामान्य से 3-4 डिग्री बढ़कर 20-23 डिग्री तक रह सकता है। जबकि शेष सभी संभागों में 19-21 डिग्री तक जाएगा। वहीं, पूरे प्रदेश में दिन में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ते हुए सामान्य से 2-4 डिग्री अधिक 36 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और दक्षिण-पूर्वी हवाओं के मिलने के कारण पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। आखिरी दिनों में रीवा और शहडोल संभागों में न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि भोपाल सहित शेष पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-4 डिग्री अधिक 23-26 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। जबलपुर संभाग में दिन में 37-40 डिग्री जबकि भोपाल सहित शेष पूरे प्रदेश में सामान्य से 3-5 डिग्री बढ़कर 38-42 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहेगा। दक्षिण-पूर्वी हवाओं के आने से जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। आखिरी दिनों में ग्वालियर, चंबल, इंदौर, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग के साथ राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल और हरदा जिलों में 3-4 दिन तक लू भी चल सकती है।

माता-पिता ने छोड़ा नाबालिग का साथ तो दरिंदा बना सगा भाई, दुष्कर्म के लिए अब 20 साल की काटेगा सजा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। राजधानी के निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली तीन नाबालिग बहनों को पहले पिता, फिर मां ने साथ छोड़ दिया। माता-पिता के साथ छोड़ने के कारण बहनों को बच्चों के एक आश्रय स्थल में रखा गया, जहां विवाद के बाद उन्हें भाई को सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद तो भाई दरिंदा बन गया और जब मौका मिलता, अकेला पाता वह छोटी बहन के साथ हैवानियत करने लगा। आरोपी ने रिश्तों को कलंकित करते हुए कई बार नाबालिग बहन की आबरू लूटी। पीड़िता की दादी को घटना पता चली तो उसने पुलिस ने प्रकरण दर्ज कराया। अब भोपाल जिला अदालत ने दरिंदे भाई को नाबालिग बहन से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय किशोरी माता-पिता के साथ निशातपुरा थाना क्षेत्र में रहती थी। घर में उसके अलावा बड़ा भाई और दो छोटी बहनें थीं। वर्ष 2023 में माता-पिता में विवाद हुआ और पिता उसकी मां को छोड़कर चला गया। कुछ दिन मां ने पिता का इंतजार किया, इसके बाद मां ने तीनों बहनों को अनाथ आश्रम नित्य सेवा सोसायटी को सौंपकर वह भी चली गई। पीड़िता अपनी दो छोटी बहनों के साथ सोसायटी में रहने लगी। चूंकि वह अनाथ आश्रम में नई-नई थी, इसलिए कुछ दिनों बाद ही उसका विवाद वार्डन से हो गया। इसके बाद वार्डन ने उसके परिजनों से संपर्क किया। कुछ दिन बाद उसका बड़ा भाई मिलने पहुंचा तो सोसायटी ने उसके द्वारा विवाद करने का हवाला देकर उसे भाई के साथ भेज दिया। चूंकि माता-पिता दोनों के जाने के बाद बड़ा भाई अकेले रह रहा था, इसलिए वह बहन को निशातपुरा थाना क्षेत्र में ही रहने वाली दादी के यहां छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता दादी के साथ रहने लगी। 8 जून 2023 को किशोरी का भाई उससे मिलने आया तो दादी घर पर नहीं थी। इसके बाद युवक ने सगी बहन के साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर किसी को नहीं बताने को बोलकर चला गया। इसके बाद तो भाई की लत लग गई और आए दिन आता और जब दादी घर के अंदर नहीं होती तो वह छोटी बहन के साथ दरिंदगी करता और चला जाता।

व्यवहार बदला तो दादी को पता चला

आए दिन दरिंदगी का शिकार होने के कारण पीड़ित किशोरी का व्यवहार बदलने लगा। वह सहमी-सहमी रहने लगी। बात-बात पर झल्लाने लगी। इसके बाद दादी को पता चला कि बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही है। इसके बाद दादी ने निशातपुरा थाने जाकर पीड़िता के भाई के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया। भोपाल जिला अदालत ने पीड़िता के बयान, साक्ष्यों व पुलिस की विवेचना के आधार पर दरिंदे सगे भाई को 20 वर्ष कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से लोक अभियोजन अधिकारी दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की थी।

फरार टीआई की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा- अपराध गंभीर, राहत नहीं मिलेगी

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल में भ्रष्टाचार के मामले में फरार चल रहे निलंबित टीआई जितेंद्र गढ़वाल की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं होगा। गढ़वाल पर आरोप है कि उन्होंने एएसआई पवन रघुवंशी के जरिए रिश्वत की डील कराई थी। मामले में टीकमगढ़ के पार्षद अंशुल उर्फ मोना जैन और बीजेपी नेता मोइन खान भी फरार हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने एएसआई पवन रघुवंशी को पांच लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन वह बाद में फरार हो गया। जांच में पता चला कि रिश्वत की यह डील 25 लाख रुपये में तय हुई थी, जिसमें पहली किश्त के रूप में पांच लाख रुपये दिए जा रहे थे। टीआई जितेंद्र गढ़वाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि जिस ऐशबाग थाने में वह पांच मार्च की सुबह तक पदस्थ थे, उसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उनके साथ एएसआई पवन रघुवंशी, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र और पार्षद अंशुल उर्फ मोना जैन को भी आरोपी बनाया गया है। भोपाल के प्रभात चौराहे स्थित एक बिल्डिंग में ठगी का कॉल सेंटर संचालित हो रहा था। पुलिस ने 23 फरवरी को यहां दबिश दी थी और संचालक अफजल खान के बेटे को गिरफ्तार कर छोड़ा था। मामला तूल पकड़ने के बाद 3 मार्च को एफआईआर दर्ज कर अफजल को गिरफ्तार किया गया। जांच में करोड़ों रुपये के लेनदेन और 26 लोगों के नाम सामने आए, जो ठगी में शामिल थे। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि इस मामले में टीआई जितेंद्र गढ़वाल, एएसआई पवन रघुवंशी, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र और प्रधान आरक्षक मनोज को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू की गई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

11 करोड़ कैश, 52 किलो सोना होगा सरकारी खजाने में जमा

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। आयकर विभाग ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर की कार से जब्त 11 करोड़ रुपये नकद और 52 किलो सोने को सरकारी खजाने में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका कारण यह है कि सौरभ, चेतन और शरद जायसवाल ने अब तक इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं किया है।

यदि आगे भी कोई स्वामित्व साबित नहीं होता, तो आयकर विभाग इसे सरकारी संपत्ति घोषित कर सकता है।

जेल में पूछताछ, लेकिन नहीं मिला जवाब

सौरभ, शरद और चेतन, जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, से आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने जेल में कई दौर की पूछताछ की। हालांकि, किसी ने भी यह स्पष्ट नहीं किया कि इतनी बड़ी नकदी और सोना किसका है। चेतन का कहना है कि कार उसके नाम पर थी, लेकिन उसका उपयोग सौरभ करता था। वहीं, सौरभ का बयान है कि उसका जब्त संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है।

सरकारी संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया शुरू अधिकारियों के अनुसार, जब तक इस संपत्ति का वास्तविक मालिक सामने नहीं आता, तब तक आयकर विभाग इसे सरकारी खजाने में जमा करेगा। स्टेट बैंक में जमा नकदी और सोने की अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके आधार पर इसे सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है।

लोकायुक्त से नहीं मिली पूरी जानकारी

इस मामले में लोकायुक्त, ईडी और आयकर विभाग के बीच समन्वय की कमी भी उजागर हुई है। आयकर विभाग ने लोकायुक्त से सौरभ के खिलाफ हुई जब्ती की पूरी जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक सभी जानकारियां साझा नहीं की गई हैं। इस संबंध में आयकर विभाग दोबारा पत्र भेज सकता है।

क्या है अप्रेजल रिपोर्ट?

अप्रेजल रिपोर्ट किसी भी मामले की पूरी जांच, मूल्यांकन और आकलन की विस्तृत रिपोर्ट होती है। इसमें जब्ती से लेकर संपत्ति के स्वामित्व और कानूनी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। यह रिपोर्ट आयकर विभाग द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेजी जाती है।

भोपाल मंडल के 9 रेलवे स्टेशन हुए ग्रीन, मिला आईएसओ 14001 सर्टिफिकेशन

सिटी चीफ भोपाल।

भोपाल। पश्चिम मध्य रेलवे का भोपाल मंडल यात्रियों को बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल रेल यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में भोपाल मंडल के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों भोपाल, बीना, इटारसी, गंजबासौदा, गुना, नर्मदापुरम, सांची, शिवपुरी और विदिशा को हाल ही में आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

जाने क्या है आईएसओ 14001 ईएमएस प्रमाणपत्र आईएसओ 14001 ईएमएस प्रमाणपत्र एक

अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रणाली है जो रेलवे स्टेशनों को स्वच्छता, जल संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और हरित निर्माण तकनीकों के बेहतर प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके तहत रेलवे स्टेशनों पर पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, जिससे यात्रियों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण मिलता है।

इसलिए मिला यह प्रमाण पत्र

भोपाल मंडल के स्टेशनों पर साफ-सफाई के उच्च मानक सुनिश्चित करने, कचरे का वैज्ञानिक और व्यवस्थित निपटान, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) की व्यवस्था, ऊर्जा बचत हेतु अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यात्री सुविधाओं में जल-संरक्षण उपायों को अपनाकर जल की बचत की जा रही है। भोपाल, बीना, इटारसी, गंजबासौदा, गुना, नर्मदापुरम, सांची, शिवपुरी और विदिशा स्टेशन पर लागू इन पहल से यात्रियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित हुआ है। यात्रियों को साफ-सुथरे प्लेटफार्म, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय और बेहतर वायु गुणवत्ता प्राप्त हो रही है, जिससे उनकी यात्रा सुखद और आरामदायक बन रही है।

रेलवे यात्रा होगी और बेहतर

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने कहा कि आईएसओ प्रमाणन यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया कदम है। इससे भोपाल मंडल में रेलवे यात्रा को और बेहतर, आरामदायक एवं पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में रेलवे यात्रियों को और भी उन्नत, आधुनिक और पर्यावरण हितैषी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सम्पादकीय

अभारतीय पैंगोलिनः प्रकृति का संतुलनकर्ता, पर संकट में अस्तित्व

जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, सभी जीव अपनी-अपनी तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ भोजन इकट्ठा करते हैं, जबकि अन्य अपने शरीर को सर्दी से सुरक्षित रखने के विशेष उपाय करते हैं। इस बीच, भारतीय पैंगोलिन, जिसे आमतौर पर चिंटीखोर के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा अद्वितीय जीव है जो सबका ध्यान आकर्षित करता है। यह न केवल प्रकृति का एक मूल्यवान अंग है, बल्कि अपनी अद्भुत आदतों और जीवनशैली से विज्ञान और वन्यजीव प्रेमियों को भी आश्चर्यचकित कर देता है।

जब आप पहली बार भारतीय पैंगोलिन को देखते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने कवच पहने हुए छोटे डायनासोर को जीवंत कर दिया हो। इसके शरीर पर केराटिन से बने कठिन और मज़बूत शल्क होते हैं, जो इसे शिकारियों से सुरक्षित रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शांत और शर्मीला जीव अपनी दुनिया में खोया रहता है, मानो ठंडी सर्दी की रातों का आनंद ले रहा हो।

भारतीय पैंगोलिन दिन के बजाय रात का जीव है, जो दिन के समय गहरी मिट्टी में स्थित अपने बिल में विश्राम करता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता है, वह बाहर निकलकर भोजन की खोज करता है। ठंडी सर्दियों में, जब तापमान गिरता है, तो यह अपने ठिकाने को और गहरा कर लेता है, जिससे वह ठंडी हवाओं से बचा रहता है। इसका आश्रय न केवल ठंड से सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि शिकारियों से भी इसे सुरक्षित रखता है।

यह अपने आहार के लिए चुपचाप निकलता है, जिसमें मुख्य रूप से चींटियां और दीमक शामिल होते हैं। पैंगोलिन की लंबी और चिपकने वाली जीभ इन्हें पकड़ने में विशेष रूप से प्रभावी होती है। भोजन करने की उसकी प्रक्रिया अद्वितीय है; वह अपने शक्तिशाली पंजों का प्रयोग करते हुए दीमकों के बिल्लों और चींटियों के अंडों को बाहर निकालता है और फिर अपनी जीभ की मदद से उन्हें खाना शुरू करता है।

अब यह सोचने वाली बात है कि सर्दियों में, जब चींटियों और दीमकों की संख्या घट जाती है, तो वह क्या करता है। लेकिन पैंगोलिन का शरीर इस परिवर्तित परिस्थिति के लिए अनुकूलित है, जिससे वह सीमित भोजन के साथ भी जीवित रहने की क्षमता रखता है।

पैंगोलिन को प्रकृति का संतुलनकर्ता कहना बिना वजह नहीं है। यह स्तनधारी जंगलों में चींटियों और दीमकों की जनसंख्या का नियंत्रण करता है। यदि पैंगोलिन न हो, तो ये छोटे जीव तेजी से *Proliferate* कर सकते हैं, जिससे फसलों और पेड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार, पैंगोलिन का अस्तित्व न सिर्फ जंगलों, बल्कि कृषि क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हालांकि, आज यह अद्भुत प्राणी गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। शिकार और अवैध व्यापार के कारण भारतीय पैंगोलिन की जनसंख्या निरंतर घटती जा रही है। इसकी खाल और शल्क का उपयोग पारंपरिक दवाओं और गहनों में होता है, जिससे यह शिकारियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है। यह निंदनीय है कि इस शांति प्रिय जीव को मानव की लालच के कारण अपनी जान खोनी पड़ रही है। यदि आपको लगता है कि पैंगोलिन केवल चींटियों का सेवन करता है, तो आप गलत हैं। इसकी अन्य आश्चर्यजनक विशेषताएं भी हैं। अपने बचाव के लिए, पैंगोलिन अपने आपको एक गेंद की तरह लपेट लेता है। इसके कठोर कवच इसे शिकारियों से सुरक्षित रखने का एक प्रभावशाली उपाय है। यह अपनी लंबी जीभ का उपयोग करके अधिक खाना खा सकता है, जिसकी लंबाई कभी-कभी उसके शरीर से भी अधिक होती है! पैंगोलिन अपने पंजों का उपयोग करते हुए इतनी तेजी से जमीन में खुदाई करता है कि वह कुछ ही मिनटों में गहरी सुरंग बना लेता है।

भारतीय पैंगोलिन न केवल हमारी जैव विविधता का हिस्सा है, बल्कि यह पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करता है। हमें इस जीव को बचाने के लिए जागरूक होना होगा। सरकार और गैर-सरकारी संगठन इसे बचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जब तक आम लोग इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक यह अद्भुत जीव खतरे में रहेगा। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी फैलानी होगी। इसके प्राकृतिक आवास को बचाना और अवैध शिकार को रोकना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

तकनीकी शिक्षा में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य

हिंदी या मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पाने वाले बच्चों के सामने महाप्रश्न यह है कि डिग्री लेने के बाद उनका भविष्य क्या है? कौन उन्हें नौकरी देगा? क्या सरकारें ऐसे स्नातकों को आरक्षण देंगी? दो अलग अलग माध्यमों से शिक्षित डॉक्टरों और इंजीनियरों में आपसी तालमेल कैसे बैठेगा? हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़े डॉक्टर, इंजीनियरों को कहीं तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से दोयम तो नहीं मान लिया जाएगा?

तमिलनाडु की डीएमके सरकार और केन्द्र की मोदी सरकार के बीच जारी 'भाषा युद्ध' के तीसरे चरण में तमिलनाडु ने भारतीय मुद्रा रुपए का राष्ट्रीय चिन्ह बदलकर उसे तमिल वर्णमाला के अक्षर 'र (रूपाई) में बदल दिया है। इसके पहले केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीएमके के हिंदी विरोध को राजनीतिक बताते हुए कहा था कि राज्य सरकार पहले वहां तमिल भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो व्यवस्था करें।

शाह के इस आदेशात्मक 'सुझाव' से यह बहस फिर तेज हो गई है कि क्या देश में अंग्रेजी के विकल्प के रूप में हिंदी व भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा संभव है, अगर है तो कैसे? हालांकि मप्र जैसे राज्य ने ढाई साल पहले मेडिकल की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित करने की अच्छी पहल की थी। कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसकी शुरूआत हुई है, लेकिन यहां प्रश्न स्व-भाषा अभिमान और मातृ भाषा में सुगम शिक्षा से कहीं ज्यादा जटिल और व्यावहारिक चुनौतियों से भरा है।

यह काफी हद तक सम्प्रेषण की एकरूपता से जुडा है एवं ग्लोबल भी है। दरअसल स्थानीय भाषाओंमें तकनीकी शिक्षा का भविष्य उन छात्रों के भविष्य से तय होगा, जो इस माध्यम में पढ़कर निकले हैं। यह शिक्षा उन छात्रों के पेशेवर ज्ञान की अद्यतनता, प्रामाणिकता, कॅरियर और आजीविका से कितनी जुड़ पाती है तथा तकनीकी एवं प्रौदयोगिकी क्षेत्र उनका कितना स्वीकार करते हैं, इस पर काफी कुछ निर्भर है।

हकीकत में ऐसे नवाचारों को विद्यार्थियों के स्तर पर भी खास प्रतिसाद नहीं मिल पाया है। हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी पुस्तकों की बहुत कमी है। जो अनुवाद हुए हैं, उनकी प्रामाणिकता तथा छात्रों की उनमें रूचि भी अहम है। ऐसी पुस्तकों को लेकर प्रकाशकों का रवैया भी बहुत उत्साहजनक नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु में भी कुछ शिक्षा संस्थानों में तमिल में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई है, लेकिन उसका प्रतिसाद लगभग वैसा ही है कि जैसे मप्र में हिंदी में इन विषयों की पढ़ाई को लेकर है। अव्वल तो बहुत ही गिने चुने विद्यार्थी ही हिंदी या अन्य भारतीय भाषा को इन विषयों की पढ़ाई का माध्यम चुनते हैं, क्योंकि उनके लिए इस संदर्भ में स्वभाषा प्रेम से ज्यादा रोजगार की चिंता होती है।

वर्तमान में देश के लगभग सभी मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है। ऐसे में उनका आपसी संवाद भी बना रहता है। दूसरी तरफ हिंदी या क्षेत्रीय भाषा माध्यम से पढ़कर आने वाले विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी में विषय को समझना और आत्मसात करना कठिन होता है। उन्हें अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी होती है। कई बार मानसिक तनाव और कई बार न्यून ग्रंथि का शिकार भी होना पड़ता है।

हिंदी या मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा पाने वाले बच्चों के सामने महाप्रश्न यह है कि डिग्री लेने के बाद उनका भविष्य क्या है? कौन उन्हें नौकरी देगा? क्या सरकारें ऐसे स्नातकों को आरक्षण देंगी? दो अलग अलग माध्यमों से शिक्षित डॉक्टरों और इंजीनियरों में आपसी तालमेल कैसे बैठेगा? हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में पढ़े डॉक्टर, इंजीनियरों को कहीं तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से दोयम तो नहीं मान लिया जाएगा?

अगर नौकरी मिल भी गई तो इन विषयों में वैश्विक स्तर पर हो रहे शोध और अद्यतन ज्ञान उन्हें अपनी भाषा में कैसे, कब और कितना मिलेगा? यहां तक कि हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में उनकी मार्क शीट भी कितने लोग समझेंगे? यूं भी कारपोरेट में हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए कोई जगह नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी और उससे सम्बद्ध कुछ कॉलेजों तथा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तिरूनेलवेली में मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल में होती है। राज्य सरकार भी तमिल में पढ़े इंजीनियरों में से 20 फीसदी को नौकरी में प्राथमिकता देती है। लेकिन वहां भी तमिल में इंजीनियरिंग पढ़ने को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई देता, क्योंकि निजी कंपनियां ऐसे इंजीनियरो को नौकरी देने को लेकर ज्यादा उत्सुक नहीं रहतीं। क्योंकि उन्हें ऐसे छात्रों के इंजीनियरिंग ज्ञान के परफेक्शन पर संदेह रहता है।

उधर, विद्यार्थियों को लगता है कि क्षेत्रीय भाषा का अभिमान अपनी जगह है, लेकिन भारत में रोजगार जगत इसकी कोई खास वकत नहीं है। इसके अलावा तकनीकी शब्दावली का तमिल या अन्य क्षेत्रीय भाषा में ठीक से अनुवाद उपलब्ध न होना भी है। कुछेक मामलों में मेडिकल की पढ़ाई भी तमिल में करने की प्रायोगिक सुविधा है। लेकिन छात्रों के सामने बड़ी कठिनाई तमिल में तकनीकी किताबों का अभाव है। यही वजह है कि क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली सीटों पर अधिकांश छात्र प्रवेश नहीं लेते।

यूपी, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि का अनुभव भी यही रहा है। एआईसीटीई का डाटा कहता है कि हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा माध्यम वाली इंजीनियरिंग की ज्यादातर सीटें खाली रहती हैं। वर्ष 2021-22 में ऐसी 80 फीसदी खाली रहीं तो 2022-23 यह आंकड़ा 53 फीसद रहा। देश में सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों को मिलाकर इंजीनियरिंग की 25 लाख सीटें हैं।

तीन साल पहले देश के 22 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने कुल 2580 सीटें हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में इंजी पढ़ने वाले छात्रों को ऑफर की थीं। मप्र की राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित मैनिट कॉलेज में 2023 में 150 छात्रों ने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए प्रवेश लिया था, लेकिन बाद में 27 छात्र ही शेष रहे।

तो क्या अमित शाह का इशारा भी महज सियासी शगूफा ही है या फिर सरकार सचमुच भारतीय भाषाओं को तकनीकी ज्ञान का वाहक बनाने के लिए संकल्पित है? यह सही है कि जो बच्चे स्कूल स्तर पर हिंदी या अपनी मातृभाषा में पढ़कर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आते हैं, उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई में काफी दिक्कत आती है। कई बार तो वे समझ ही नहीं पाते।

इसीलिए ये सोचा गया कि मेडिकल व इंजी. की किताबें भी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार की जाएं ताकि ग्रामीण परिवेश से आए विद्यार्थी विषय को आसानी से समझ सकें। मध्यप्रदेश में पहली बार अक्टूबर 2022 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी माध्यम की किताबें केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की थीं।

तर्क यही था कि जब रूसी,जापानी, जर्मन,चीनी आदि भाषाओंमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकती है तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में क्यों नहीं? क्यों हम अंग्रेजी पर ही निर्भर रहें। क्यों विदेशी भाषा का बोझ ढोते रहें?

दरअसल हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई को लेकर कई व्यावहारिक समस्याएं हैं। अभी ऐसे शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाई होती है। ऐसे में देश के किसी भी कोने का डॉक्टर या इंजीनियरिंग तकनीकी रूप से एक दूसरे की बात समझता है, सम्प्रेषित कर सकता है। अगर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इन विषयों की पढाई होगी तो वो एक दूसरे से कैसे किस भाषा में संवाद करेंगे।

मसलन तमिल माध्यम में पढ़ा छात्र उत्तर भारत के किसी डॉक्टर या इंजीनियर के कैसे बात कर सकेगा? मलयालम में बनी डीपीआर हिंदी माध्यम वाला कैसे समझेगा? क्या इन क्षेत्रों में इतना जोखिम उठाया जा सकता है? यानी हमे हर स्तर पर अनुवाद और एकरूपता की जरूरत होगी और वह हमेशा प्रामाणिक ही हो, यह जरूरी नहीं है। दूसरे, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कितनी भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी? उनका आपसी संपर्क किस भाषा में होगा।

अगर वहां अंग्रेजी की जगह हिंदी विकल्प दिया गया तो दक्षिण व अन्य गैर हिंदी भाषी राज्य उन पर हिंदी थोपने का आरोप लगा सकते हैं, जो तमिलनाडु में हो ही रहा है, इससे और नई समस्या पैदा होंगी। तमिल में शिक्षित मेडिकल प्रोफेसर उस राज्य के बाहर पढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकता।

हालांकिं हिंदी वालों के लिए कुछ ज्यादा विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम वालों जितने नहीं। सबसे बड़ी समस्या इन विषयों के अद्यतन ज्ञान की भी है। दुनिया में इस विषयों से सम्बन्धित शोध पत्र अंग्रेजी में तुरंत अनूदित हो जाते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं तक पहुंचने में बहुत समय लगता है या फिर वो हो ही नहीं पाते।

हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा वाला विद्यार्थी या डॉक्टर अथवा इंजीनियर नए शोधों के बारे में जल्दी कैसे जानेगा? उसे उन शोध पत्रों का अनुवाद दूसरी भाषा में होने तक कितना इंतजार करना पड़ेगा? इससे भी बड़ी समस्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी संपर्क और संवाद की है। बेशक दुनिया में अंग्रेजी सबकी भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी डेढ़ अरब लोग इसे बोल या समझ सकते हैं। वैसे यह सवाल पहले अंडा या मुर्गी की तरह है। हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी विषय पढ़ाना शुरू ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगा। इसका इलाज यही है कि आ रही दिक्कतों का समाधान ढूंढा जाए लेकिन गुणवत्ता से किसी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। अनुवाद की कड़ियों को मजबूत किया जाए। उसे पूर्णतः विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाया जाए। यह बहुत कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं बशर्ते कि वैसी संकल्पशक्ति और साफ नीयत हो।

गौरैयाः जैव विविधता का आधार, संरक्षण की ज़रूरत

चौबीस से चालीस ग्राम तक की फुदकती हुई छोटी-सी गौरैया हमारी जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन का बहुत बड़ा आधार है। लेकिन दुनियाभर में बढ़ते शहरीकरण, मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन, खेतों में इस्तेमाल की जाने वाले कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग तथा अपने प्राकृतिक आवासों की कमी के कारण दुनिया में गौरैया की संख्या तेजी से घट रही है। साल 2010 में लुप्त होती गौरैया को बचाने के लिए और दुनिया को उसके महत्व को बताने के लिए 'नेचर फॉर एवर सोसायटी' के संस्थापक मोहम्मद दिलावर द्वारा विश्व गौरैया दिवस मनाये जाने की शुरुआत भारत में हुई। पक्षियों के पैसर वंश की गौरैया का जीवनकाल आमतौर तीन साल का होता है। गौरैया की कई दो प्रजातियां हैं लेकिन दो सबसे मशहूर हैं एक घरेलू गौरैया और दूसरी यूरेशिया वृक्ष गौरैया।

गौरैया का भोजन मुख्यत: अनाज के दाने और फसलों के कीड़े-मकोड़े हैं। ये अनाज के दाने घरों में गिरे पड़े हुए भी हो सकते हैं और खेतों में बालियों में लगे भी हो सकते हैं, खासकर ज्वार और बाजरा के खुली बालियों में से गौरैया खूब मन से अपना भोजन चुरा लेती है। गौरैया आमतौर पर घरों में या घरों के आसपास ही रहती है, जिसे लोग आसानी से पहचान लेते हैं। गौरैया 46 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से उड़ती है। यह छोटी-सी चिड़िया पूरे दिन घरों के आसपास फुदकती रहती है। गौरैया के बारे में जानने लायक कई तथ्यों में से एक यह भी है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता और पौधों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। गौरैया उत्सर्जन के माध्यम से बीजों को फैलाने तथा वनस्पति को बढ़ावा देने में मदद करती है।

हाल के दशकों में गौरैया के लगातार खत्म होने का कारण शहरीकरण, कृषि पद्धतियों में बदलाव और पेड़ों की बड़ी तादाद में हुई कटाई है, जिसके कारण गौरैया को घोसला बनाने के लिए अनुकूल जगह मिलनी मुश्किल हो गई है। इसी तरह खेतों में बड़े पैमाने पर कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस कारण कीड़े-मकोड़े नहीं हो रहे और जो होते भी हैं, वो तेजी से खत्म हो जाते हैं। इस कारण गौरैया को अपना स्वाभाविक भोजन मिलने में मुश्किल हो रही है।

भारत में पायी जाने वाली घरेलू चिड़िया दरअसल गौरैया है। इसका वैज्ञानिक नाम पैसर डोमेस्टिकस है। यह पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में घरों के आसपास पायी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा यही घरेलू गौरैया ही मिलती हैं, लेकिन गौरैया की पांच अन्य प्रजातियां भी थोड़ी-थोड़ी संख्या में अलग-अलग एक या दो प्रदेशों में पायी जाती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में वाइट थ्रोटेड स्पैरो इसका वैज्ञानिक नाम जोनोट्रिचिया अल्बीकोलिस है। इसकी आवास प्राथमिकताएं पर्वतीय क्षेत्र हैं, इसलिए यह भारत में मुख्यत: जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पायी जाती है। राजस्थान और गुजरात में कुछ मात्रा में चेस्ट नट-सोल्डरेड पैट्रोनास गौरैया भी पायी जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैट्रोनिया जैन्थोकोलिस है। यह आमतौर पर सूखे जंगलों या स्क्रब लैंड में पायी जाती है।

'द स्टेट ऑफ इंडियन बड्स' रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत की कुल चिड़ियों में 28 चिड़िया ही ऐसी हैं जो ठीकठाक संख्या में हैं या बढ़ रही हैं। 643 चिड़ियों का सही-सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो सबसे खतरनाक आंकड़ा चिड़ियों को लेकर है, वह यह है कि 78 चिड़िया या तो खत्म हो चुकी हैं, या इतनी कम है कि नजर नहीं आ रही हैं। 64 चिड़ियों की प्रजातियां ऐसी हैं, जो तेजी खत्म हो रही हैं। अगर दुनियाभर में मौजूदा चिड़ियों की प्रजातियों की बात करें तो 942 प्रजातियों की जानकारी है, जिसमें 299 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं या उसके कागार में है। चिड़ियों की इस हालत में गौरैया का धीरे-धीरे कम होना खतरनाक है, क्योंकि गौरैया महज एक चिड़ियाभर नहीं है बल्कि यह धरती में खेती की विविधता को बरकरार रखने और उसे कोने-कोने में फैलाने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए विश्व गौरैया दिवस दुनिया के हर संवेदनशील और धरती को बने रहने के बारे में सोचने वाले इंसान से उम्मीद करता है कि वह गौरैया संरक्षण के लिए उनके उपयुक्त आवास की व्यवस्था करेंगे और गौरैया को निरंतर अपना भोजन और आवास उपलब्ध रहे, उसकी चिंता करेंगे। विश्व गौरैया दिवस हर साल किसी विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल गौरैया दिवस का विषय या थीम है- 'होप फॉर स्पैरो' यानी गौरैया के लिए आशा। इस थीम का मुख्य उद्देश्य गौरैया संरक्षण के प्रति आशा और सकारात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

बढ़ता कृषि उत्पादन, गिरती महंगाई अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

तिलहन उत्पादन खरीफ में 21 फीसदी और रबी में 2 फीसदी बढ़ने की संभावना है। फल और सब्जी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने के बाद देश में खाद्य मुद्रास्फीति काफी नीचे आई है और ऐसा बेहतर कृषि उत्पादन की बदौलत हो सका है। बुधवार को जारी आंकड़े बताते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति यानी खुदरा महंगाई की दर फरवरी में घटकर केवल 3.61 फीसदी रह गई है। पिछले साल जुलाई के बाद यह सबसे कम आंकड़ा है। खाद्य मुद्रास्फीति की दर भी कम होकर 3.75 फीसदी रह गई, जो मई 2023 के बाद सबसे कम है। खाद्य मुद्राफीति में पिछले साल अक्टूबर के बाद से ही गिरावट आ रही है। उस महीने यह उछलकर 10.87 फीसदी तक पहुंच गई थी। उसके कारण समग्र मुद्रास्फीति दर भी कुछ समय तक ऊंची बनी रही और भारतीय रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत जटिलताएं पैदा हो गई थीं। खाद्य मुद्रास्फीति की दर कुछ समय तक नीचे ही रह सकती है। 2024-25 में प्रमुख फसलों के उत्पादन के हाल में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान उम्मीद जगाते हैं। खरीफ में पिछले साल से 7.9 फीसदी अधिक खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है और रबी की खाद्यान्न उपज में 6 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है। गेहूं, चावल और मक्के की फसल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन भी बढ़ा है। इसमें मोटे अनाज, तुअर और चना शामिल हैं। तिलहन उत्पादन खरीफ में 21 फीसदी और रबी में 2 फीसदी बढ़ने की संभावना है। फल और सब्जी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। प्रथम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में बागवानी फसल उत्पादन 36.21 करोड़ टन रह सकता है, जो 2023-24 की तुलना में 2.07 फीसदी ज्यादा होगा। पिछले साल मॉनसून अच्छा रहने और फिर सर्दी सामान्य रहने के कारण इस साल उत्पादन में रिकॉर्ड इजाफा हो सकता है। सकल घरेलू उत्पाद के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4.6 फीसदी वृद्धि हो सकती है। पिछले साल वृद्धि का आंकड़ा 2.7 फीसदी था। अग्रिम अनुमान पिछले दिनों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्य मूल्य खुद ही नीचे आएंगे। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि 2025-26 में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 4.2 फीसदी रहेगी, जो चालू वित्त वर्ष में 4.8 फीसदी है। 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति की औसत दर 8.4 फीसदी रही जबकि औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर 5.3 फीसदी थी। उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण समग्र मुद्रास्फीति की दर केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से ऊपर रही और इससे परेशान परिवार मनचाही चीजों पर खर्च नहीं कर सके। इससे कुल खपत भी सुस्त हो गई। 2023-24 में कुल मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय में खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी ग्रामीण इलाकों में 47.04 फीसदी और शहरी इलाकों में 39.7 फीसदी रही। कम आय वाले परिवार अपनी मासिक आय का और भी बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। ऐसे में कृषि उत्पादन बढ़ने से कुल उत्पादन तथा मांग बढ़ेगी और वृद्धि को गति देने में मदद मिलेगी। खाद्य कीमतों में तेज गिरावट और कम मुख्य मुद्रास्फीति के कारण नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश बनती है। मगर घटती महंगाई और बढ़ते खाद्य उत्पादन को देखकर नीति निर्माताओं को कृषि क्षेत्र में अरसे से पसरी चुनौतियों से नजर नहीं हटानी चाहिए।

कटनी में दिल दहला देने वाली वारदात

सौतेली मां ने मासूम बेटी को उतारा मौत के घाट

सुनील यादव । सिटी चीफ
कटनी, कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र खितौली पुलिस चौकी अंतर्गत उटीन टोला निवासी एक सौतेली मां ने अपनी ही 7 वर्षीय सौतेली बेटी की गले में रस्सी के सहारे गला घोट मौत के घाट उतर दिया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरही पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को अरेस्ट कर उसे पूछताछ कर रही है पूछताछ में उसने इस वारदात को अंजाम देना कबूला है। कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि यह पूरी वारदात जिले के बरही थाना क्षेत्र खितौली पुलिस चौकी अंतर्गत उटीन टोला का है जहां एक एक 7 साल की मासूम जिसका नाम नैना है उसकी सौतेली मां नंदनी कुशवाहा ने इस

लिए गले में रस्सी के सहारे गला दबा मौत के घाट उतर दिया क्यों कि उसकी 7 साल की सौतेली बेटी नैना अपने सौतेले नन्हे भाई को खिला रही थी उसी दौरान वह जमीन पर गिर गया और रोने लगा था जिससे आक्रोषित हो सौतेली मां नंदनी कुशवाहा ने 7 साल के मासूम नैना के गले में रस्सी से गला दबा मौत के घाट उतार दिया कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने यह भी बताया कि वह शुरू से ही अपनी सौतेली बेटी नैना को नहीं चाहती थी इस लिए वह हमेशा अपनी सौतेली बेटी नैना से दूरी बनाए रखी हुई थी और इसी के चलते उसने अपने सौतेली बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बरही पुलिस ने आरोपी सौतेली मां नंदनी कुशवाहा को अरेस्ट कर उसे पूछताछ की इस पूछताछ के दौरान आरोपी सौतेली मां ने कबूल किया है कि उसने अपने सौतेली 7 साल की नैना के गले की रस्सी के सहारे गला घोट मौत में घाट उतरा है, पुलिस ने सौतेली मां नंदनी कुशवाहा को अरेस्ट कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है।

प्रधानमंत्री आवास को रौंदेगा वन विभाग का बुलडोजर ...?

विभागीय अफसरों ने की दलित, आदिवासी महिलाओ से मारपीट

मोहम्मद मुनीर । सिटी चीफ
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक योजना है, इसके ज़रिए, शहरों और गांवों में रहने वाले ग़रीब परिवारों को घर मुहैया कराए जाते हैं. इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण इलाकों में घर बनाए जाते हैं एमपी के शहडोल जिले में भी पीएम आवास योजना अंतर्गत लाखो घर बनाये गए है लेकिन जिले का वन विभाग दलितों आदिवासियो के पीएम आवास को उजाड़ने की हिमाकत कर रहा है, इसके पीछे का तर्क वनभूमि में आदिवासी दलितों का कब्ज़ा बताया जा रहा है लेकिन पुस्तैनी काबिज इन लोगो को वनाधिकार पट्टा योजना से लाभान्वित क्यों नहीं प्रदान किया गया, और जब प्रधानमंत्री आवास बन रहा था तो वन अमला सो रहा था इस मामले में आदिवासियो से अफसरों ने अपनी सीमाएं लांघते हुए महिलाओ से मारपीट कर दी है केवल उसके पीछे 20 - 20 हजार की रिश्वत ना दिए जाने को लेकर ढहाए जा रहे जुल्म सितम है।

पढ़े पूरी खबर .....शहडोल।एमपी के इस जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों पर शहडोल का वन विभाग कहर बरपाने की हिमाकत करने की रणनीति बना रहा है इसके पीछे की कहानी क्या है इस बात की पुष्टि दलितों की शिकायत से होती है, फर्ज करो किसी भी के घर पर अचानक अलसुबह लाव लश्कर लेकर सरकारी अमला घर गिराना है खाली करो वरना जेल में नजर आओगे, दहाड़ता हुआ दिखाई दे, यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं यह हकीकत है कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्यौहारी के अफसरों की जिन्होंने न सिर्फ तालिबानी हुकरानो की याद को ताज़ा कर दिया है बल्कि यह साबित करना चाहते है कि अब चंद मुठ्ठी भर अफसर आदिवासी बाहुल्य इलाका शहडोल से आदिवासी, दलितों को आबादी खत्म कर के रहेंगे, तभी तो अफसरों को ना महिलाओ की मर्यादा का ख्याल रहा है ना ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री का सपना हर गरीब के सर पर छत की फ़िक्र। वरना होली पर्व के ठीक दो दिन पूर्व बीते 12 मार्च 2025 की सुबह दलितों आदिवासियो के सपना उजाड़ने बुलडोजर लेकर नहीं पहुंचते।इसकी भनक जिले के तीन विधानसभा से निर्वाचित आदिवासी विधायकों को जाने कैसे नहीं है समझ से परे है। दरअसल मामला वन परिक्षेत्र ब्यौहारी का है जहा वन विभाग का अमला पचास वर्षो से अधिक समय से खेती किसानी कर किसी कदर गुजर बसर कर रहे है जिनको हालही में पक्की छत प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत मिली है, और इस छत को ढहाने वन अमला पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है मामला अत्यधिक संवेदनशील है जिसे स्थानीय प्रशासन से लेकर जिले प्रशासन ने नजर अंदाज करते हुए दलितों आदिवासियो के साथ नाइंसाफी कर दी है।

दलितों की नहीं सुनवाई.... इस मामले में पीड़ितों में दुर्घटिया बाई, सुमित्रा चर्मकार, आशा बाई, ममता, नीता सहित 20 से अधिक की संख्या में बच्चे बुजुर्ग जारी घोर अन्याय की शिकायत लेकर थाना ब्यौहारी की देहलीज में माथा पीटते इन्साफ की गुहार लगाईं लेकिन वन अमले और पुलिस महकमों की सेटिंग इनकी रपट लिखने से पहले गायब सर्वर और नादरत ऑपरेटर आड़े आ गया, लेकिन घंटो इंतज़ार करने के बाद इनके हाथ कुछ ना लगा लेकिन वन विभाग के अफसरों के आते ही पुलिसिया कलम सरपट 5 जी से 10 जी की रफ़्तार में रपट लिखने लगी।इस बार पुलिसिया कलम दलितों आदिवासियो को सरकारी कार्य में बाधा वाला प्रशासनिक ब्रम्हास्त्र चलाकर दलितों आदिवासियो को चारो खाने चित्त करने का षड्यंत्र रचा।

सितम गरीबो पर, रसूख़दारो पर रहम.... गौरतलब है इस मामले में पुख्ता प्रशासनिक जांच की जाए तो येपि वन परिक्षेत्र में दलितों आदिवासियो का पुस्तैनी कब्ज़ा खेती किसानी दखल था तो पूर्व में हटाया क्यों नहीं गया।अब जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और गरीब को छत नसीब हो चुकी है तो इसमें सरासर इस वन परिक्षेत्र में निगरानी में भारी चूक है जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग को लेनी चाहिए।हम आपको बता दे की यह कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्यौहारी के वही अफसर है जिनके नाक के नीचे नहीं ठीक बगल में वनभूमि को ही एक रसूखदार ने कब्ज़ा कर तीन मंजिला इमारत तान दी उसका बाल भी नहीं बाक़ा कर पाए।इधर गरीब बेबस पर प्रशासनिक ताकत दिखा कर कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्यौहारी में अफसरों का दोहरी कानून व्यवस्था के तहत कार्यप्रणाली लागू है चरितार्थ कर दिया है।जिसका ज़वाब तो देना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ तो इल्ज़ाम है बग़ावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी सी होती है।

इनका कहना है।

खुटेलाटोला के रहने वाले है हम 80 साल से अधिक रहते हो गया हमको, यहाँ नरेंद्र मोदी जी ने जो

दुर्गघटिया बाई, प्रधानमंत्री आवास हितग्राही
ग्राम हिडवाह, ब्यौहारी

मेरा बाप दादा के ज़माने से यहाँ घर है हमारे पास खेती किसानी के अलावा कोई जीविकापार्जन का साधन नहीं है, आज अफसर घर गिराने की बात कर रहे है।हम कहा जायेगे।

समयलाल, पीड़ित
ग्राम हिडवाह, ब्यौहारी

हमारा प्रधानमंत्री आवास बना है डिप्टी साहब सुबह सुबह बुलडोजर लेकर गिराने आये, मैंने विरोध किया तो मेरा हाथ मरोड़ा चमारिन हटो यहाँ से नहीं तो जेल भेजा दूंगा।

पीड़ित महिला
प्रधानमंत्री आवास हितग्राही, हिडवाह, ब्यौहारी

ब्यौहारी थाने में पुलिस कर्मचारी अधिकारी ने हमको भगा दिया, कहा यहाँ से चले जाओ वरना तुम सबको जेल में डाल देंगे ।

दिनेश साकेत, पीएम आवास हितग्राही
ग्राम हिडवाह, ब्यौहारी

पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर ही सभी की समस्याएं हल होगी - भगत सिंह वर्मा

पृथक राज्य के लिए युवा शक्ति आए आगे - भगत सिंह वर्मा

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, काशीराम की 91वीं जयंती के अवसर पर देहरादून रोड रविदास छात्रावास पर एक बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि काशीराम का सपना था कि देश की आजादी का लाभ सभी को तब होगा जब देश के आखिरी पायदान पर खड़ा गरीब, किसान, मजदूर, वंचित, शोषित, आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और यह सब सत्ता में आने पर भी संभव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि किसानों, गरीबों, मजदूरों, वंचितों, शोषितों, दबे-कुचले लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश का विभाजन जरूरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिलों को मिलाकर बनने वाला पृथक पश्चिम प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे विकसित और उन्नतशील राज्य होगा। उत्तर प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है। दुनिया के मात्र तीन देश भारत, चीन और अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होने के कारण यहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। पूरा प्रदेश गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुंडागर्दी एवं अव्यवस्था की चपेट में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले सरकार को 80% राजस्व देते हैं जबकि यहां के विकास पर मात्र 19% धन खर्च किया जाता है। सबसे अधिक राजस्व देने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी एम्स नहीं है। उत्तर प्रदेश में दो एम्स हैं दोनों पूर्वांचल में हैं। आईआईटी पूर्वांचल में है। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण होने पर यहां शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी और सभी को निःशुल्क होगी। सहारनपुर और मेरठ में एम्स की स्थापना होगी, मेरठ में हाईकोर्ट और राजधानी होगी। और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय देश में ही नहीं दुनिया में कतर सिंगापुर, लक्जमबर्ग देश से भी अधिक होगी। बैठक में काशीराम को याद करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। और इस अवसर पर रोहित गौतम को भारतीय किसान यूनियन वर्मा का प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया गया। भगत सिंह वर्मा ने कहा कि आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि युवा शक्ति को आगे आकर अपनी समस्याओं को हल करने के लिए पृथक पश्चिम प्रदेश निर्माण के संघर्ष में भागीदारी करनी चाहिए। बैठक को राष्ट्रीय सलाहकार रजत शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित नीरज कपिल, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मवीर चौधरी, प्रदेश महामंत्री आसिम मलिक, प्रदेश मंत्री संदीप एडवोकेट, मंडल मीडिया प्रभारी दुष्यंत सिंह, जिला संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह एडवोकेट, सौरभ कुमार, विशाल कुमार, रोहिताश चौटाला, भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गौतम ने संबोधित किया।

देवबंद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का त्यौहार

त्यौहार के मौके पर युवाओं के साथ-साथ बच्चें, महिलाएं और बुजुर्ग एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आये

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, देवबंद नगर में रंगों का त्यौहार होली पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्यौहार के मौके पर युवाओं के साथ-साथ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी खुशियां मनाते हुए और एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर बधाई देते हुए नजर आये। तमाम तरह के रंगों से सराबोर बच्चे तो खासतौर से बड़े उत्साहित दिख रहे थे। बच्चें आने-जाने वाले लोगों पर रंग और अबीर-गुलाल की बरसात करते हुए भी नजर आये। लोगों ने इस मौके पर अपने-अपने घरों पर आए दोस्तों और मेहमानों की गुझिया, मिठाई, चाट-पकौडी आदि से मेहमान नवाजी की। होली के अवसर पर गाये जाने वाले गीतों की भी इस मौके पर खूब धूम रही। रंग-बिरंगे लोग नाचते-गाते और गली-मौहल्ले में घूम-घूमकर लोगों को अबीर-गुलाल लगाकर एक-दूसरे को गले लगाकर होली की बधाई देते नजर आये। गुरूवार को होलिका दहन के समय लोग खासकर महिलाएं धार्मिक रीति-रिवाज के साथ होलिका की पूजा और अन्य अनुष्ठान करती देखी गयीं।होली के मौके पर सभी ने एक-दूसरे को शुभकामनायें दी और सबकी सुख एवं समृद्धि की कामना की। देवबंद निवासी अमित सिंघल एडवोकेट, नितिन गुप्ता, विशाल गर्ग, निखिल अग्रवाल, गगन मित्तल, मुकेश अग्रवाल, राजू सैनी ने कहा कि रंगों का त्यौहार होली, सामाजिक सौहार्द का पर्व है और लोगों के जीवन में खुशी, उत्साह एवं आशा का संचार करता है। कहा कि उमंग और उल्लास का यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विविधता में निहित राष्ट्रीय चेतना को और शक्ति प्रदान करे। कहा कि रंगों का त्योहार होली आपसी मेल-जोल और खुशियों का प्रतीक है। यह समाज के सभी वर्गों और विभिन्न परम्पराओं को मानने वाले लोगों को जोड़ता है। कहा कि खुशियों और रंगों का यह त्यौहार नई उमंग के साथ जीवन जीने का संदेश देता है। साथ ही एकता, समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। उधर रंगों से सराबोर लोगों ने एक-दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर, मोबाइल फोन, ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर होली के पावन-पर्व की शुभकामनाएं दी। दिनभर युवाओं की टोलियों को गुलाल और रंगों से होली खेलते देखा गया। इस दौरान देवबंद नगर के विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

सामाजिक संस्था विकास एवं सुरक्षा समिति द्वारा परम्परागत होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर । देवबंद, देवबंद नगर की राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदभाव की प्रतीक सामाजिक संस्था विकास एवं सुरक्षा समिति द्वारा परम्परागत आयोजित होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ रेलवे रोड स्थित एक रेस्टोरेन्ट में आयोजित किया। समारोह में लगभग सभी सम्प्रदाय के लोगों ने सम्मिलित होकर वक्ताओं एवं शायरों के विचारों से आनन्द की अनुभूति प्राप्त की।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व गृहमंत्री मौ0 सईदुज्जमा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारत देश के हर व्यक्ति को भाईचारा और आपसी प्रेम हर हाल में कायम रखना होगा। उन्होंने कहा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोगों के बीच ऊँच- नीच एवं छोटे-बडे का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी जातियों एवं वर्गो के लोग एक साथ मिलकर इस पर्व का आनन्द लेते हैं । समाजसेवी सतीश गिरधर ने जो लोग अपने क्षेत्र व देश-प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाडने का प्रयास करते हैं उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे लोग गिने चुने हैं जिनसे सावधान रहने की आवश्यकता है और आपसी एकता व सद्भाव से ही देश व प्रदेश का विकास सम्भव है। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन चौ0 राजपाल सिंह, लोकप्रिय चिकित्सक डा0डी0के0जैन, अन्तर्राष्ट्रीय शायर डा0 नवाज देवबन्दी, व्यापारी नेता दीपकराज सिंघल, सलीम कुरैशी, इरम उस्मानी, समिति के संरक्षक कुलदीप कुमार छाबडा, अशोक गुप्ता, जनारदन दास त्यागी, ब्रिजेश कंसल आदि ने भी अपने विचार प्रकट किये। इसी के साथ प्रसिद्ध शायर जहाज देवबन्दी व नईम अख्तर ने अपनी गजलों से समारोह को खुशनुमा बना दिया । समिति की ओर से दोनो शायरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे समिति अध्यक्ष सी.ए. संदीप गुप्ता ने सभी आमंत्रित अतिथिगण का आभार प्रकट किया। संचालन कोषाध्यक्ष जर्रार बेग एवं कार्यक्रम संयोजक अंसार मसूदी ने संयुक्त रुप से किया। इस अवसर पर मुख्य रुप से डा0 आर0 पी0 खोराना, डा0 मुजम्मिल हसन, नजम उस्मानी, अरुण त्यागी, रेहान अहमद, विनय त्यागी, पंकज गुप्ता, अंकित जैन, आदेश त्यागी एड., राजकुमार जाटव, ओमवीर सिंह, विवेक तायल आदि काफी संख्या में नगर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जीवन के उच्चतर मूल्यों का बोध होना ही शिक्षा है- गुलशन नागपाल

बौद्धिक संपदा अधिकार विषयक पर राष्ट्रीय सेमिनार हुई आयोजित

गौरव सिंघल । सिटी चीफ
सहारनपुर, मां शाकुम्बरी विश्वविद्यालय में बौद्धिक संपदा अधिकार विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए मोटिवेशनल स्पीकर एवं उद्यमी गुलशन नागपाल ने कहा कि शिक्षा वही है, जो व्यक्ति को उच्चतर मूल्यों का बोध करा सके। शिक्षा केवल जीवकोपार्जन और ऊंचे पैकेजेस के लिए ही नहीं बल्कि उच्चतर संस्कारों के लिए भी होनी चाहिए। सेमिनार में उपस्थित रिसर्च स्कॉलर्स एवं देश के विभिन्न प्रांतों से आमंत्रित विषय के अग्रणी वक्ताओं एवं शिक्षा जगत के अग्रणी जनो को संबोधित करते हुए मुख्य व्यक्ता के रूप में गुलशन नागपाल ने आह्वाहन करते हुए कहा कि जीवन में केवल उन्हीं वस्तुओं, विचारों, कला और संगीत को प्रतिपादित करे जिनको मानवता के उत्थान और विकास के लिए उपयोग किया जा सके वरना उन्नासवीं शताब्दी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक 'अल्फ्रेड नोबेल' की तरह अपने आविष्कारों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए विश्विद्यालय की उपकुलपति प्रोफेसर श्रीमती विमला वाई ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर बल दिया। सेमिनार में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन से राम जी सुनेजा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से डॉ.सिद्दीकी, प्रोफेसर फिरोज,वित्त नियंत्रक डॉ.सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रोफेसर विनोद कुमार,डॉ. वी के गुप्ता, सेमिनार संयोजक डॉ ऋषिपाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया विश्व गौरैया दिवस अभियान चलाया

लोगों को किया जा रहा है जागरूक

अश्विनी वालिया । सिटी चीफ
कुरुक्षेत्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के मीडिया प्रभारी अश्विनी कुमार वालिया ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत सरकार के केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री राम दास अठावले की प्रेरणा से देशभर में तथा हरियाणा में विश्व गौरैया दिवस अभियान चलाया जा रहा है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस है। इस अभियान का मकसद घरेलू गौरैया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इनके संरक्षण के लिए प्रयास करना है। गौरैया की लुप्त होती प्रजाति को बचाना है। उन्होंने बताया कि गौरैया जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। गौरैया की संख्या में लगातार कमी आने की वजह, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, आधुनिक शहरीकरण, और प्रदूषण है। मीडिया प्रभारी ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया हरियाणा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुंडली के नेतृत्व में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि हरियाणा की तरक्की में योगदान दिया जा सके। प्रदेश के हर जिले में पार्टी का विस्तार किया जा रहा है। पार्टी का लक्ष्य हर दलित, पिछड़े व अहसहाय लोगों की मदद करना है।

फिर एक बार न्यायालय में हुई ठाकुर शिवकुमार किसान हितेषी पैनल की जीत

बुरहानपुर

प्रत्यायुक्तों के सहयोजन मुद्दे के निराकरण के बाद ही होगा, संचालको का निर्वाचन।

बुरहानपुर नि.म.प्र. - नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नवल नगर के बहुचर्चित निर्वाचन प्रक्रिया में फिर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेष पारित हुये है। जिसमें दिनांक 11.03.2025 को आदेष पारित करते हुये, शक्कर कारखाने के निर्वाचन अधिकारी को निर्देषित किया है कि, उसके द्वारा दिनांक 09.03.2025 को की गयी प्रत्यायुक्तो के सहयोजन की प्रक्रिया का पुन: निराकण करें। जिसके पश्चात ही दुसरे चरण मे होने वाले संचालको के निर्वाचन सम्पन्न करें। इस प्रकार निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनायी गयी प्रत्यायुक्तो के निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने संचालको के निर्वाचन को रोक दिया गया है। जिससे शक्कर कारखाने के निर्वाचन को नया मोड आ गया है, किसानो मे हर्ष की लहर दौड़ गयी है। उल्लेखनीय है कि, नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाना नवल नगर झिरी, बुरहानपुर में निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। जिसमें निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहयोजन हेतु दिनांक 09.03.2025 को सभा आयोजित की गयी जिसे कोरम का अभाव दिखाकर निवर्चान अधिकारी ने प्रत्यायुक्तो का बगैर सहयोजन किये सभा को समाप्त कर दिया। जबकी उक्त दिनांक को उज्वल पाटील जो अपने आप को संचेतक कृषक मानते है वह भी सभा को असफल करने के लिए कारखाना परिसर में उपस्थित रहे किन्तु वह सभा में उपस्थित नही रहे जिससे उनकी दोगली नैतिकता प्रकट होती हैं। उक्त सभा को निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधी के प्रावधानो के विपरीत जाकर इस सभा को कोरम के अभाव दिखाकर

समाप्त कर देने से कारखाने के हितेषी किसानो को गहरा आघात लगा, जिससे प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन हेतु पात्र पिडीत किसानों ने इस निर्वाचन प्रक्रिया के विरुध्द माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में एक संयुक्त रिट याचिका तत्काल प्रस्तुत की जिसका रिट पीटीसन नं. 8056/2025 है। उक्त याचिका के सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने किसानो द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को को गंभीरता से सुना एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनायी गयी दूषित निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुत किये दस्तावेजो एवं विधी के प्रावधानों का गंभीरता से विचार कर दिनांक 11.03.2025 को अपना आदेष पारित करते हुयें निर्वाचन अधिकारी को निर्देषित किया की वह विधिवत रुप से एवं किसानों को सहयोजन प्रक्रिया में उचित सुनवाई का अवसर देकर निराकरण करें जिसके पश्चात ही शक्कर कारखाने के संचालकों के निर्वाचन की कार्यवाही शुरु करें। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने सहयोजन की प्रक्रिया पुर्ण करने के पश्चात ही संचालकों का निर्वाचन करने के आदेष निर्वाचन अधिकारी को दिये है। जिससे सहयोजन की दूषित प्रक्रिया से पिडीत किसानों एवं कारखाना हित में प्रयास रत क्षेत्र कें किसानों में हर्ष लहर दौड गयी है। उन्होने माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेष को सत्य की जीत माना है। उल्लेखनीय है कि नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना प्रदेष का सर्वोच्च कारखाना जो निमाड के जननेता स्व. ठा. षिवकुमार सिंह ने अपनी कडी मेहनत से इसे खडा किया है। जिससे प्रत्येक्ष रुप से 8500 कृषक जुडे है, एवं हजारो बेरोजगारो को यह कारखाना रोजगार प्रदान कर रहा हैं। जिसे कई विरोधी ताकते अपने दबाव प्रभाव से हतियाना चाहते है। वर्तमान परिपेक्ष्य ठाकुर परिवार इस कारखाने को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। किसानो का मानना है कि यह कारखाना ठाकुर परिवार के हाथ मे ही रहना चाहिए जिस कारण कारखाने से जुडे समस्त किसान ठाकुर परिवार का साथ दे रहे है। इस स्थिति को देखते हुये कारखाना विरोधि ताकते शासन प्रषासन का साथ लेकर सत्ता के प्रभाव से अधिकारियों पर दबाव बनाकर कारखाने के किसानों के हितो एवं अधिकारो का हनन कर रहे है, तथा निर्वाचन को प्रभावित कर रहे है। इस परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष कारखाना विरोधि पक्ष पर कडा तमाचा है। इस आदेष को किसानो ने अपनी जीत बताकर ठाकुर पैनल की जीत निरुपित किया है।

राजस्व मंत्री ने ग्राम तकिया में आग से खेत में नष्ट हुई फसलों का किया

सीहोर

राजस्व मंत्री ने संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने के दिए निर्देश

हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है - राजस्व मंत्री श्री वर्मा

आग से 10 किसानों की लगभग 28 एकड़ की फसल हुई नष्ट

राजस्व मंत्री श्री करण सिहं वर्मा ने श्यामपुर तहसील के ग्राम तकिया में आग से नष्ट हुई खेत में खड़ी गेंहू की फसल के नुकसान का निरीक्षण किया तथा प्रभावित किसानों से भेंटकर नुकसान के बारे में जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि गत दिवस ग्राम तकिया में 10 किसानों की लगभग 28 एकड़ की फसल अग्नि दुर्घटना में नष्ट हो गई थी। आग से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है उनमें ग्राम पाटन के 07 किसान, ग्राम तकिया के 02 किसान तथा ग्राम बरखेड़ा खरेट का एक किसान शामिल है। निरीक्षण के दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने किसानों से चर्चा की और फसल में आग लगने से हुए नुकसान की हर संभव मदद के लिए कहा। उन्होंने किसानों की पीड़ा को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों की गेंहू की फसल नष्ट हुई है उन सभी किसानों को उनकी फसल का संवेदनशीलता के साथ-साथ अधिक से अधिक मुआवजा स्वीकृत किया जाए। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानो की सरकार है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी सरकार किसानों के साथ डटकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगी। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी हर पीड़ा का समाधान हमारी प्राथमिकता है। जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें उचित मुआवजा मिलेगा। राजस्व मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की देरी न हो और किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाए। निरीक्षण के दौरान श्री सत्री महाजन, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, नायब तहसीलदार श्री अर्पित मेहता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इंदौर जिले में 3226 लोकेशनों में होगी वृद्धि.

कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण एवं प्रस्तावों पर चर्चा हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न

इन्दौर

इंदौर जिले में कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण एवं प्रस्तावों पर चर्चा हेतु कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वय डॉ. अमरेश नायडू और श्री दीपक शर्मा, जिला पंजीयक, उप पंजीयक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिये 3226 लोकेशनों के लिये वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिये राज्य शासन को भेजा जायेगा। बैठक में बताया गया कि पंजीयन एव मुद्रांक विभाग राज्य शासन की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। दस्तावेज के पंजीयन से प्राप्त होने वाली आय में अचल सम्पत्ति हेतु तैयार किये जाने वाली गाईड लाईन दरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंदौर ऐसा जिला है जो प्रदेश में अचल संपत्तियों के पंजीयन से होने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व देता है। महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त माह अप्रैल 2024 से माह फरवरी 2025 तक पंजीबध्द दस्तावेजों के आंकडों को अवलोकन से प्राप्त जानकारी अनुसार कई लोकेशन पर प्रचलित गाईड लाईन से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे है। इसको देखते हुए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 में दिये गये प्रावधानों के तारतम्य में

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीयन उप जिले यथा इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर जिले में स्थित अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य की दरों के प्रस्ताव एवं दरों के निर्धारण, गाईड लाईन मूल्य के प्रस्तावों पर चर्चा हेतु उक्त बैठक आयोजित की गई। इन्दौर जिले में गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा ऐसे आंकडे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें प्रचलित गाईड लाईन से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे है। उक्त आंकड़ों का अध्ययन कर संबंधित लोकेशनों हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृद्धि के लिये प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं।

406 नई लोकेशनें वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाईन में इन्दौर जिले की लगभग 1112 लोकेशनों को आपस में मर्ज कर लगभग 407 नवीन लोकेशनें बनाई गई है। जिससे संपदा 2.0 में पोलीगोन की मैपिंग आसान हुई जिससे उन संबंधित लोकेशन पर दस्तावेज का पंजीयन सरलता से होगा।

जिले में 3226 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाईन की कुल 4680 लोकेशन में से 3226 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। शेष लोकेशनों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है। इनमें से 202 लोकेशन में 10 प्रतिशत तक, 275 लोकेशन में 11 से 20 प्रतिशत तक, 907 लोकेशन में 21 से 30 प्रतिशत तक, 904 लोकेशन में 31 से 50 प्रतिश?त तक, 636 लोकेशन में 51 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। अन्य 303 लोकेशनों में भी वृद्धि प्रस्तावित की गई है। पंजीयन उप जिले यथा इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर में 240 नवीन कॉलोनियों / लोकेशनों का नाम आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की गाईड लाईन में राजस्व संग्रहण को दृष्टिगत रखते हुऐ जोडा जाना प्रस्तावित किया गया है। उक्त नवीन कॉलोनियों / क्षेत्रों एवं आसपास / समीप स्थित कॉलोनियों/क्षेत्रों एवं पंजीबद्ध किये जा रहे दस्तावेजों में संगणित दरों के समकक्ष प्रस्तावित की गई हैं। जिले में इस तरह 240 नवीन कालोनियों/लोकेशन में वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

किसान भाई शीघ्रता से कराए अपना गेहूं उपार्जन का पंजीयन- कलेक्टर श्री संदीप जी आर

सागर

किसान भाई शीघ्रता से कराए अपना गेहूं का उपार्जन का पंजीयन कराए। उक्त अपील कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने जिले के किसान भाइयों से की है। कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने जिले में समर्थन मूल्य पर रबी सीजन फसलो के क्रय हेतु किए जाने वाले प्रबंधो की समीक्षा कर उपार्जन कार्य शुरू होने से पहले हरेक केन्द्र पर बुनियादी आवश्यकताओं की तमाम पूर्ति सुनिश्चित हो। एक भी केन्द्र ऐसा नहीं होना चाहिए जहां उपार्जन शुरू होने के उपरांत आवश्यक सामग्री की पूर्ति नहीं की गई हो। जैसे वारदाना, तौलकांटा, स्टेनशील, सिलाई मशीन, धागा इत्यादि की पूर्ति उपार्जन कार्यो से पहले हो। कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने गेंहू उपार्जन की अवधि और समर्थन मूल्य के संबंध में बताया कि गेंहू प्रति क्विंटल, 2425 रूपए घोषित किया गया है जबकि 175 रूपए बोनस राशि देने की भी घोषणा की गई है जिसकी जानकारी कृषको तक पहुंचाने के निर्देश संबंधितो को दिए है। किसानो

के पंजीयन अवधि के संबंध में बताया गया कि 20 जनवरी से पंजीयन कार्य शुरू हुआ है जो 31 मार्च तक जारी रहेगा। किसान पंजीयन हेतु निर्धारित स्थल व शुल्क एवं नि:शुल्क केन्द्रो की जानकारियां दी गई है। किसान पंजीयन व पंजीकृत रकवा सबसे कम पंजीयन वाले केन्द्र, पंजीकृत किसानो का सत्यापन, गिरदावरी से गेंहू के रकवे का मिलान एवं सत्यापन, उपार्जन केन्द्रो का विवरण, सर्वेयरो की व्यवस्था व उनके दायित्व गेहूं एफएक्यू मापदण्ड, वारदाने पर समिति एवं कृषक कोड अंकन व्यवस्था, गेंहू रकवा एवं उत्पादन का तुलनात्मक व वार्षिक आंकडे, वारदाना व्यवस्था, गोदामो का सत्यापन, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कार्पोरेशन और जिले की क्षमता एवं रिक्त क्षमता की जानकारी, रबी उपार्जन 2024-25 के परिवहन भुगतान की समीक्षा की गई है। बैठक में गेंहू पंजीयन के अलावा चना, मसूर, सरसो के पंजीयन हेतु किए जाने हेतु प्रबंधो के संबंध में भी जानकारियां प्रस्तुत की गई है इसके अलावा उचित मूल्य दुकानो के लिए आवंटित खाद्यान्न के उठाव व परिवहन की अद्यतन जानकारियों से अवगत कराया गया है।

अशासकीय विद्यालयों में पुस्तकें, यूनीफार्म तथा अन्य सामग्री विक्रय कराये जाने पर अंकुश लगाये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

गुना गुना जिले में शासकीय, अशासकीय विद्यालय संचालित है, इनमें अशासकीय स्कूलों/शैक्षणिक संस्थाओं में काफी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत है। शिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर कई अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा शाला में

पूर्व लेखक एवं प्रकाशक के नाम तथा मूल्य के साथ कक्षावार पुस्तकों की सूची विद्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करें और शाला के विद्यार्थियों को ऐसी सूची मांगने पर उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण इन पुस्तकों को उनकी सुविधा अनुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें। प्रत्येक स्कूल प्रबंधक प्राचार्य अपने स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगने वाली पाठ्य पुस्तकों तथा प्रकाशक की जानकारी को वेबसाइट E-Mail ID deoguna-mp@nic.in पर दिनांक 25 मार्च 2025 तक अनिवार्यत: प्रेषित करेंगे एवं एक हार्डकापी जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना के कार्यालय में जमा करायेगें। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होना चाहिये। विद्यालय के सूचना पटल पर यह भी अंकित किया जावे कि किसी दुकान विशेष से सामग्री क्रय करने की बाध्यता नहीं है। कहीं से भी पुस्तकें/ यूनिफार्म व अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की जा सकती है। पुस्तकों के अतिरिक्त शालाओं द्वारा यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपियों आदि भी उन्हीं की शालाओं से उपलब्ध/ विक्रय कराने का प्रयास नहीं किया जावेगा। विद्यालय के गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगा। विद्यालय की स्टेशनरी/ यूनिफार्म पर विद्यालय का नाम प्रिन्ट करवाकर दुकानों से क्रय करने अथवा एक विशिष्ट दुकान से यूनिफार्म/ पाठ्य पुस्तके बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। विद्यालय द्वारा उनके यहां संचालित कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें, बिना पाठ्यक्रम परिवर्तन हुये विगत वर्ष की प्रचलित पुस्तकों एवं प्रकाशकों को परिवर्तित कर प्रतिवर्ष उनके स्थान पर मंहगी पुस्तकें खरीदने के लिए पालकों पर दबाव बनाया जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निजी विद्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा। प्रत्येक विद्यालय में कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एवं प्रवेश किस दिनांक से दिनांक तक होंगे की सूचना का प्रचार-प्रसार करना अनिवार्य होगा। जिससे पालकों एवं प्रवेश कराने वाले पालकों तक सूचना प्राप्त हो सकें। संबंधित क्षेत्र के उप खण्ड मजिस्ट्रेट, एवं जिला शिक्षा अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से दिनांक 13 मार्च 2025 से 12 मई 2025 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

मदिरा के अवैध संग्रहण व विक्रय के मामले में 13 प्रकरण दर्ज

हरदा कलेक्टर श्री आदित्य सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग के दल ने गत दिवस मदिरा के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरुद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री रितेश कुमार लाल ने बताया कि आबकारी विभाग के दल ने हरदा के खेड़ीपुरा मोहल्ला, टंकी मोहल्ला, सरदार मोहल्ला, बैरागढ़, कुल्हरदा, ग्राम नीमगाँव, लोलांगरा, आमासेल व सिराली मे दबिश देकर कुल 48 पाव देशी शराब, 41 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब एवं 720 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 13 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 83740 रूपये है।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 25 मार्च को होगा

हरदा समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 25 मार्च को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 मार्च को समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में से आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दी जा रही सेवाओं एवं ''समाधान एक दिवस'' जैसे विषयों की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पंजीयन व राशि के भुगतान से संबंधित प्रकरणों, हेण्डपम्प के रखरखाव, संबल योजना, राशन कार्ड, सरपंच सचिव, रोजगार सहायक व अन्य के द्वारा योजना का लाभ दिलाने हेतु अनुचित राशि की मांग तथा छात्रवृत्ति संबंधित लंबित शिकायतों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 मार्च को जिला अस्पताल का लोकार्पण करेंगे

विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा

राजगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 16 मार्च, 2025 रविवार को राजगढ़ के भ्रमण पर आएंगे। अपने भ्रमण के दौरान डॉ. यादव यहां 40 करोड़ रूपये की लागत से नवनिर्मित जिला चिकित्सा भवन का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान शौर्य स्मारक का भी लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में दोपहर 01:00 बजे स्टेडियम ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न निर्माण कार्यक्रम का भूमिपूजन एवं हितग्राहियों को लाभांवित किया जाएगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं राजगढ़ जिला प्रभारी मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कौशल विकास एवं रोजगार विभाग श्री गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास श्री नारायण सिंह पंवार, सांसद श्री रोडमल नागर, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चन्दर सिंह सौंधिया, विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव, विधायक खिलचीपुर श्री हजारीलाल दांगी, विधायक नरसिंहगढ़ श्री मोहन शर्मा, दिशा के सदस्य एवं जिला भाजपा अध्यक्ष श्री ज्ञानसिंह गुर्जर एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्री विनोद साहू होंगे।।

आपदा के समय आप सभी धैर्य संयम का सामना कर आपदा का सामना करें - श्री प्रांशु सिंह

सागर आपदा के समय आप सभी धैर्य संयम का सामना कर आपदा का सामना करे। उक्त विचार जिला आपदा समिति के द्वारा आयोजित शासकीय मेनपानी हाई स्कूल में आयोजित आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान के अंतर्गत जागरूक श्री प्रांशु सिंह ने व्यक्त किये । इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर एवं आपदा प्रबंधन की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती यादव सहित अन्य अधिकारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। आपदा प्रबंधन के जानकार श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि कोई भी आपदा निर्धारित समय पर नहीं आती अचानक ही आपदा आती है और घटना घट जाती है घटना घटने की समय सभी लोगों को धैर्य संयम रखते हुए उसका सामना करना चाहिए और उससे बचाव करना चाहिए। श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि यदि कि कहीं भी आगजनी की घटना घटती है तो इसके बचाव लिए भी अनेक उपाय हैं लेकिन बचाओ इस समय कर पाते हैं जब आदमी संयम एवं धैर्य

रखें और अपनी पूरी मानसिकता के साथ बचाव को करके घटना को डाला जाए और आगजनी की घटना को पर काबू पाया जाए श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि इसी प्रकार पानी से आने वाली आपदाओं में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि पानी आग एवं हवा से आने वाली आपदाओं पर हमें विस्तार से इसकी बचाव के लिए कार्य करने होंगे और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जान जनता किसी की बचाव के लिए जानकारी देना होगी श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जो आपदा प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूल कॉलेज में आपदा से बचाव के लिए जो जन जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसके माध्यम से अवश्य ही जन जन तक इसकी जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार श्री प्रांशु सिंह ने कहा कि अधिकतर देखा जाता है कि ग्राम में सर्पदंश होने के बाद व्यक्ति झाड़ फूंकी के कार्य में लगता है जबकि सर्वप्रथम उसको इलाज की आवश्यकता होती है इसलिए सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए इसी प्रकार वर्षा ऋतु में अनेक जगह जल भराव के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है और बाढ़ में फंसने से अनेक जन हानि भी होती है उन्होंने बाढ़ एवं जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए अनेक सुझाव भी बताएं। संयुक्त कलेक्टर एवं आपदा प्रबंधन की नोडल अधिकारी श्रीमती आरती यादव ने कहा कि कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा संपूर्ण जिले में आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा आपदा से बचाव के लिए जनजाति अभियान प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से नुक्कड़ नाटक, स्कूल कॉलेज में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं।

ग्राम तकिया के प्रभावित किसानों से मिले विधायक श्री

सीहोर

विधायक श्री सुदेश राय ने श्यामपुर तहसील के ग्राम तकिया में आग से नष्ट हुई खेत में खड़ी गेंहू की फसल के नुकसान का निरीक्षण किया तथा प्रभावित किसानों से भेंटकर नुकसान के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद दिलाने के लिए कहा। निरीक्षण के पश्चात लौटते समय उन्होंने गांव के बच्चों को चॉकलेट वितरित कीं तथा एक बालिका के पास स्कूल के लिए ड्रेस एवं जूते नहीं होने पर तत्काल क्रय करने के लिए राशि प्रदान की।

लंबे अंतराल के बाद ग्रामीणों की मांग स्वीकृत

उज्जैन

सेदरी आक्या फंटा रोड को स्वदेश ने बनाया था लगातार मुख्य मुद्दा

विधायक चौहान का धन्यवाद

लंबे अंतराल के बाद ही सही पर अंततोगत्वा से ग्राम वासियों को जिसमें किसानों राहगीरों के साथ ही खासकर उच्च अध्ययन के लिए आक्या जागीर पढ़ने जाने वाले छात्र छात्राओं की मांग को स्वीकृति मिलीं है, इस स्वीकृति के बाद क्षेत्र के वर्तमान विधायक डॉ तेज बहादुरसिंह चौहान को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई और धन्यवाद भी मिल रहा है, हालांकि अभी रोड को बजट में स्वीकृति मिली है और टेंडर प्रक्रिया से साथ कार्य प्रारंभ होने का अभी इंतजार है ! सेदरी से आजा घंटे तक का यह रोड लगभग 2 किलोमीटर का है और ग्रामीण इस रोड की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं कई बार इस रोड को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया और उसका मुख्य कारण बारिश के समय में रोड अत्यधिक खराब होने के कारण किसने राहगीरों और छात्र-छात्राओं को आने वाली दिक्कतें बनता था जिसको स्वदेश के द्वारा प्रमुखता से लगातार मुद्दा बनाया जाता रहा और इसका परिणाम हुआ कि अंतोगत्वा वर्तमान बजट में इस रोड को स्वीकृति मिली है ! यहां ग्रामीणों में इस बात को लेकर खुशी है की पूर्व में कहीं जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस रोड को लेकर बार-बार आश्वासन दिए गए किंतु वर्तमान विधायक के द्वारा इसे स्वीकृत करवाया गया जिसके लिए उन्हें धन्यवाद भी मिल रहा है ! इस रोड को लेकर से के पूर्व सरपंच प्रतिनिधी घनश्याम सेकवाडीया लंबे समय से प्रयासरत रहे ओर अपने सरपंच कार्यकाल के दौरान जब भी कोई जन प्रतिनिधी गांव में आते या सेकवाडीया किसी जनप्रतिनिधि से मिलते तो इस रोड की मांग अवश्य करते, वही वर्तमान सरपंच रामचरण वर्मा भी रोड निर्माण के लिए संभव प्रयास करते रहे ! वर्तमान में रोड के स्वीकृत होने से ग्रामीणों ओर राहगीरों में अपार खुशी है, ओर अब रोड के कार्य प्रारंभ होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे है !

आसपास के जन को करना होगा सहयोग सेदरी से आजा जागीर फंटा की ओर जाने वाला यह रास्ता जहां रोड के दोनों और किसानों के खेत हैं यहां आस-पास के किसानों को इस रोड के निर्माण के दौरान सहयोग करने की अपेक्षा रहेगी यदि यह आसपास के किस रोड के निर्माण के दौरान रोड के उपयोग में आने वाली जगह को लेकर सहयोग करते हैं तो यह रोड आसानी से बन सकता है यदि कहीं गतिरोध उत्पन्न हुए ऐसी स्थिति में रोड के निर्माण को पुणे कहीं ना कहीं ग्रहण लग सकता है क्योंकि ऐसा एक बार पूर्व में हो चुका है जब सैलरी से बड़ौदा तक रोड का निर्माण हुआ था उसे दौरान इस रोड के लिए भी भूमि का चिन्हांकन हुआ था किंतु बाद में वह नहीं बना !

कार्य प्रारंभ होने का रहेगा इंतजार लंबे इंतजार के बाद सेदरी से आक्याजागीर फंटे तक लगभग 2 किलोमीटर रोड को स्वीकृति मिली है, इस रोड के लेकर ग्रामीणों की लंबे समय से मांग करते आ रहे थे और पूर्व में भी कई जनप्रतिनिधियों ने इस रोड को लेकर प्रयास कर रहे थे किंतु लंबे अंतराल के बाद अब जाकर इस रोड को स्वीकृति मिली है, हालांकि अब ग्रामीणों को रोड के कार्य प्रारंभ होने का इंतजार है, जब यह रोड बनकर तैयार हो जायेगा तब जाकर ग्रामीणों की वास्तविक मांग पूरी होगी !

सोनतलाब मे मारु कुमावत समाज द्वारा सामुहिक विवाह सम्मेलन की बैठक रखी गई

धार सरदारपुर

दिनांक 14.03.25 को कुमावत समाज सामूहिक सम्मेलन सोनतलाव में बैठक राखी गई है इस कमेटी में अध्यक्ष एवं सचिव सदस्य की।कमेटी बनाई गई है अध्यक रामचन्द्र जी (पटेल) जांगड़े सचिव मंशाराम जी खटोरे महेश चंदौर कोषाध्यक्ष नारायण जी दत्तोले प्रताप जी दुबे **समस्त सदस्या गण तुलसीराम कुमावत महेंद्र चंदौर** जितेंद्र जांगड़े गिरधारी जांगड़े आशाराम चंदौर बालकृष्ण चंदौर अशोक कुमावत मुकेश ओसवाल लचीराम जांगड़े राजेश चंदौरे पंडरी दतौले ओमप्रकाश जांगड़े हरिभाई दत्तौले सुरेश चंदौरे जगदीश चंदौरे प्रवीण कुमावत मनोज जांगड़े सुभाष चंदौरे आशीष चंदौरे मनीष चंदौरे आशाराम जांगड़े विजय चंदौरे आशाराम कुमावत राकेश कुमावत मोहिना कुमावत हरिओम कुमावत संजय कुमावत परसराम कुमावत गणेश कुमावत प्रशांत कुमावत कैलाश दत्तोले धर्मेंद्र कुमावत शिवराम कुमावत अशोक दत्तौले श्याम दत्तोले विक्की कुमावत गोपाल चंदौरेदिनेश टाक नरेंद्र दुबे संदीप चंदौरे दिनेश कुमावत गोपाल दत्तोले गणेश कुमावत महेन्द्र बाबूलाल राकेश कुमावत राधेश्याम दत्तोले समस्त ग्रामवासी सोनलाव

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भ्रमण के प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया

राजगढ़ जिले में 16 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के भ्रमण से संबंधित कार्यक्रम स्थलों का कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री महीप किशोर तेजस्वी ने भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखीं। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं सीईओ जिला पंचायत ने हेलीपेड, जिला अस्पताल एवं स्टेडियम ग्राउण्ड कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के सभाकक्ष से अधिकारियों की बैठक लेकर सौपे हुए दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए।।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने अधिकरियों के दल के साथ गेर मार्ग का निरीक्षण किया

इंदौर । इंदौर में परम्परागत रूप से निकलने वाली रंगपंचमी की गेरों के आयोजन की व्यापक तैयारियां जारी है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आज अधिकारियों के दल के साथ गेर मार्ग का निरीक्षण किया। इंदौर में 19 मार्च रंगपंचमी के अवसर पर रंगारंग गेर निकलेंगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री शविम वर्मा, अपर पुलिस आयुक्त श्री अमित सिंह, एडीएम श्री रोशन राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने गेर मार्ग के निरीक्षण की शुरूआत टोरी कार्नर चौराहे से की। इसके बाद वे निर्धारित गेर मार्गों पर पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जल्द से जल्द मार्ग की मरम्मत कर दें। विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। विद्युत के तारों को आवश्यकता अनुसार ऊंचा करें। डीपी पर भी सुरक्षा के प्रबंध रखें। पूरे मार्ग पर सभी आवश्यक बंदोबस्त सुसुनिश्चित कर ली जाये। कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाये। व्यवस्थाओं को समयसीमा में पूरा करें। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रखें जायें। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि पूरे मार्ग पर निगरानी के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएंगे। साथ ही कंट्रोल रूम भी बनाया जायेगा। बेरिकेटिंग की भी व्यवस्था रहेगी। आकस्मिक चिकित्सा के लिये भी प्रबंध किये जा रहे हैं। निर्धारित स्थानों पर एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था भी रहेगी।

इंदौर जिले में 3226 लोकेशनों में होगी वृद्धि

कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण एवं प्रस्तावों पर चर्चा हेतु जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न

इंदौर इंदौर जिले में कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण एवं प्रस्तावों पर चर्चा हेतु कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया, वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वय डॉ. अमरेश नायडू और श्री दीपक शर्मा, जिला पंजीयक, उप पंजीयक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिये 3226 लोकेशनों के लिये वृद्धि प्रस्तावित की गई है। यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिये राज्य शासन को भेजा जायेगा। बैठक में बताया गया कि पंजीयन एव मुद्रांक विभाग राज्य शासन की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। दस्तावेज के पंजीयन से प्राप्त होने वाली आय में अचल सम्पत्ति हेतु तैयार किये जाने वाली गाईड लाईन दरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इंदौर ऐसा जिला है जो प्रदेश में अचल संपत्तियों के पंजीयन से होने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व देता है। महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त माह अप्रैल 2024 से माह फरवरी 2025 तक पंजीबध्द दस्तावेजों के आंकडों को अवलोकन से प्राप्त जानकारी अनुसार कई लोकेशन पर प्रचलित गाईड लाईन से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे है। इसको देखते हुए मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 में दिये गये प्रावधानों के तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीयन उप जिले यथा इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर जिले में स्थित अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य की दरों के प्रस्ताव एवं दरों के निर्धारण, गाईड लाईन मूल्य के प्रस्तावों पर चर्चा हेतु उक्त बैठक आयोजित की गई। इन्दौर जिले में गाईड लाईन वर्ष 2025-26 में कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा ऐसे आंकडे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें प्रचलित गाईड लाईन से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे है। उक्त आंकड़ों का अध्ययन कर संबंधित लोकेशनों हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृद्धि के लिये प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये हैं।

406 नई लोकेशनें वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाईन में इन्दौर जिले की लगभग 1112 लोकेशनों को आपस में मर्ज कर लगभग 407 नवीन लोकेशनें बनाई गई है। जिससे संपदा 2.0 में पोलीगोन की मैपिंग आसान हुई जिससे उन संबंधित लोकेशन पर दस्तावेज का पंजीयन सरलता से होगा।

जिले में 3226 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाईन की कुल 4680 लोकेशन में से 3226 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। शेष लोकेशनों में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है।

इनमें से 202 लोकेशन में 10 प्रतिशत तक, 275 लोकेशन में 11 से 20 प्रतिशत तक, 907 लोकेशन में 21 से 30 प्रतिशत तक, 904 लोकेशन में 31 से 50 प्रतिश्त तक, 636 लोकेशन में 51 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

मंत्री श्री पटेल ने खण्डवा के नर्मदानगर में किया मां रेवा उद्यान का लोकार्पण

इंदौर प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शनिवार को इंदौर संभाग के खण्डवा जिले की ग्राम पंचायत नर्मदानगर में मां रेवा उद्यान का फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर चित्र पर माल्यार्पण किया। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि आवास योजना के लिए मध्यप्रदेश में सर्वे किया गया था, जिसमें लगभग 27 लाख लोगों के नाम जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत जरूरतमंदों की मदद करना सरकार का मूलभूत कर्तव्य है। इसके लिए 3 माह पहले फिर से सर्वे शुरू किया गया है जिसमें पात्र हितग्राही का नाम जुड़वा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जरूरतमंद को छूटने नहीं दिया जाएगा एवं सभी पात्रों के लिए पक्के आवास बनावाये जाएंगे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पात्र हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएँ जैसे मकान, पानी, बिजली एवं गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं संचालित की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं संचालित की हैं वह महिलाओं के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए हैं। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि गैस कनेक्शन भी महिलाओं के नाम पर ही दिया गया है। पेन्शन व वृद्धजनों के जीवन की भी चिंता सरकार द्वारा की जाएगी।

बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाकर लगवाएं खसरे का टीका

16 मार्च को मनाया जाएगा विश्व खसरा दिवस

इंदौर। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 मार्च को विश्व खसरा दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य खसरे की गंभीरता को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना और खसरे के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी.एस. सैत्या ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि अपने-अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर बच्चों को खसरा का टीका अवश्य लगवाएं और अपने बच्चों को खसरा रोग से बचाएं। उन्होंने कहा कि खसरे का टीका लगवाने के लिए खुद जागरूक रहें तथा आसपास के लोगों को भी खसरा का टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें, जिससे भारत देश में खसरे रोग का उन्मूलन हो सकें।

गाईड लाईन के संबंध में तैयार प्रस्ताव पर आमजन से सुझाव लिये जाएंगे

इंदौर इंदौर जिले में अचल संपत्तियों के पंजीयन के लिये आज तैयार किये गये प्रस्ताव पर आमजन से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। आमजन अपने सुझाव वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय और उप पंजीयक कार्यालयों में दे सकते हैं। यह सुझाव 16 मार्च से 20 मार्च 2025 के दोपहर 3 बजे दिये जा सकते हैं। साथ ही सुझाव ई-मेल आईडी drindorew@gmail.com तथा व्हाट्सअप नंबर 9893320632 पर भी दिये जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि आज कलेक्टर श्री आशीष सिंह और विधायक श्री महेन्द्र हार्डिया की मौजूदगी में संपन्न जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में अचल संपत्तियों के पंजीयन हेतु 3226 क्षेत्र/लोकेशन में संपत्ति की गाईड लाईन बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है।

इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य हुआ प्रारंभ

किसानों का तिलक लगाकर और साफा बांधकर किया गया स्वागत सत्कार

किसानों से ही पूजन-अर्चन कराकर खरीदी कार्य का किया गया मुहुर्त

पहले दिन लगभग दो हजार क्विंटल गेहूं खरीदी गया समर्थन मूल्य पर

इंदौर । इंदौर जिले में राज्य शासन द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार आज 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहले दिन आज अपनी उपज लाने वाले किसानों का पुष्पमाला पहना-तिलक लगाकर और साफा बांधकर स्वागत-सत्कार किया गया। जिले में किसानों से ही पूजन-अर्चन कराकर खरीदी कार्य का मुहुर्त किया गया। पहले दिन लगभग दो हजार क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। जिले में कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिये व्यापक इंतजाम किये गये हैं। जिले में खरीदी के लिये 91 केन्द्र बनाये गये हैं। किसानों की सुविधा के लिए केंद्रों पर किसानों के बैठने, छाया, टेंट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। खरीदी केन्द्रों पर निःशुल्क स्लॉट बुकिंग करने हेतु हेल्प डेस्क भी बनाये गये हैं। किसानों को शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने निर्देश दिये है कि जिले में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। खरीदी का कार्य नोडल अधिकारी और अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल के निर्देशन में किया जा रहा है। अपर कलेक्टर श्री गौरव बेनल ने भी आज खरीदी केन्द्रों पर पहुंचकर खरीदी कार्य और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बताया गया कि पहले दिन 12 खरीदी केन्द्रों पर 50 ट्रालियों में आये लगभग 2 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। खरीदी केन्द्रों पर गेंहू लाने वाले किसानों का पुष्पमाला पहना-तिलक लगाकर और साफा बांधकर स्वागत-सत्कार किया गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि इन्हीं किसानों से खरीदी कार्य का मुहुर्त भी कराया गया। जिला उपार्जन समिति द्वारा जिले में किसानों के लिए पर्याप्त विगत वर्ष की भांति 91 केंद्रों का निर्धारण किया गया है। जिसमें गोदाम पर 56, स्टील साइलो बरलाई 6, विभिन्न मंडी में 4 एवं समिति स्तर पर 25 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान अपनी सुविधा से किसी भी केंद्र पर अपना निःशुल्क स्टॉल बुक करा कर अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे। गेहूं उपार्जन 2600 रुपये प्रति क्विंटल के मान से (इसमें समर्थन मूल्य बोनस सम्मिलित है) पर की जायेगी। कलेक्टर आशीष सिंह के विशेष निर्देश है कि किसानों को भुगतान में किसी प्रकार का विलंब ना हो। खरीदी तौल होने के उपरांत तत्काल समिति प्रबंधक ऑपरेटर बिल बनायें। उसके बाद उसी समय ऑपरेटर द्वारा रेडी टू ट्रांसपोर्ट किया जाए। हैंडलिंग चालान या ट्रांसपोर्ट चालान बनाया जाए एवं समस्त प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण कर स्वीकृति पत्रक बनाने की कार्रवाई नागरिक आपूर्ति नियम वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा की जाये, किसानों को भुगतान की कार्रवाई अतिशीघ्र हो सकें। जिला उपार्जन समिति द्वारा फील्ड में किसानों को पर्याप्त बैठने व्यवस्था, छाया, पेयजल, साफ-सफाई हेतु पंख छलने, क्लीनिंग मशीन, हमाल तथा तौल के लिए पर्याप्त तौल कांटे आदि सुविधा/ व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाये। किसानों का भौतिक सत्यापन जिला स्तर से करने के साथ-साथ सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि नोडल अधिकारी जो केंद्र पर बनाए गए हैं, उनसे केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध सामग्री व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन तीन दिवस में पूर्ण करा कर पालन प्रतिवेदन जिला समिति को भेजा जाये। गेहूं खरीदने के लिए कंट्रोल रूम आईपीसी बैंक इंदौर में बनाया गया है, जिसके नोडल महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के श्री आलोक जैन को बनाया गया है तथा उनके साथ एक विशेष दल लगाया गया है। वे किसानों की समस्याओं को कंट्रोल रूम 07312533200 पर प्राप्त कर शिकायत का उचित निराकरण समय सीमा में करायेंगे। गेहूं उपार्जन पंजीकृत किसानों से ही किया जाएगा। जिले में कुल 31 हजार 280 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। किसानों के पंजीयन 31 मार्च तक किए जाएंगे। किसानों से आग्रह किया गया है कि किसान समय-सीमा में अपना पंजीयन कराये ताकि उनको गेहूं बिक्री करने में कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।

हमला करने के बाद ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा- हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करो

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद यमन में हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। यह हमले लाल सागर में जहाजों पर हो रहे हमलों के खिलाफ की गई कार्रवाई का हिस्सा थे। ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के मुख्य समर्थक ईरान को भी चेतावनी दी कि वह इन विद्रोहियों को समर्थन देना तुरंत बंद कर दे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका को धमकी दी तो हम पूरी तरह से जवाब देंगे और फिर हम नरम नहीं होंगे।

ट्रंप का आदेश और हमले

शनिवार को ट्रंप ने अपने अधिकारियों को यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले करने का आदेश दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही समुद्री रास्तों पर जहाजों पर हमले बंद नहीं करेंगे तब तक वे अत्यधिक घातक बल का इस्तेमाल करेंगे।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे बहादुर सैनिक अभी अमेरिकी शिपिंग, वायु और नौसैनिक संपत्तियों की रक्षा करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों और मिसाइल सुरक्षा पर हवाई हमले कर रहे हैं ताकि नौवहन स्वतंत्रता को बहाल किया जा सके। उन्होंने हूती विद्रोहियों से कहा कि उनका समय समाप्त हो गया है और उन्हें तुरंत हमले बंद करने होंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी सजा मिलेगी।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ चेतावनी

ट्रंप ने कहा, कोई भी आतंकवादी ताकत अमेरिकी और अन्य देशों के वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाजों को जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से चलने से नहीं रोक सकती। उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दी कि वह हूती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर दे और वादा किया कि वह ईरान को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएंगे।

हूती विद्रोहियों का हमला और नुकसान

वहीं शनिवार शाम को हूती विद्रोहियों ने अपने इलाके में सिलसिलेवार विस्फोटों की जानकारी दी। सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में सना हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं के गुबार दिखाई दे रहे थे जिसमें एक बड़ी सैन्य सुविधा भी जलती हुई दिखाई दी। हालांकि नुकसान की सही जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।

कुछ दिन पहले ही हूती ने कहा था कि वे गाजा पर इजरायल की नाकेबंदी के जवाब में यमन के तटवर्ती जलक्षेत्र में इस्राइली जहाजों पर हमले फिर से शुरू करेंगे। हालांकि अब तक हूती की ओर से कोई नया हमला नहीं हुआ है।

अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन की कार्रवाई

संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन ने पहले भी यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमले किए हैं। इजरायल की सेना ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की। ट्रंप ने कहा, इन लगातार हमलों से अमेरिका और पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और निर्दोष लोगों की जान भी जोखिम में पड़ी है।

अंत में कहा जा सकता है कि यह हमले और कार्रवाई यमन में जारी संघर्ष को और भी बढ़ा सकते हैं और अमेरिका का यह कदम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़ ला सकता है।

अमेरिका ने 'हमास का समर्थन करने वाली भारतीय छात्रा का वीजा किया रद्द, लौटी स्वदेश

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही वह भारतीय छात्रा स्वदेश लौट आई है, जिसका वीजा कथित तौर पर हिंसा और आतंकवाद की वकालत करने तथा हमास समर्थित गतिविधियों में शामिल होने के कारण रद्द कर दिया गया था। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि भारतीय नागरिक रंजनी श्रीनिवासन ने एफ-1 छात्र वीजा पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में शहरी नियोजन में डॉक्टरेट की छात्रा के रूप में अमेरिका में कदम रखा था। बयान में कहा गया है कि रंजिनी आतंकवादी संगठन हमास को समर्थन देने वाली गतिविधियों में शामिल थी और विदेश विभाग ने पांच मार्च को उसका वीजा रद्द कर दिया था।

इसमें बताया गया है कि होमलैंड सुरक्षा विभाग को रंजनी का 11 मार्च का एक वीडियो मिला है, जिसमें वह स्व-निर्वासन के लिए सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) के स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करती नजर आ रही है। होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम ने बयान में कहा कि अमेरिका में रहने और पढ़ाई करने के लिए वीजा हासिल करना एक विशेषाधिकार है। उन्होंने कहा, जब आप हिंसा और आतंकवाद की वकालत करते हैं, तो आपसे यह विशेषाधिकार छीन लेना चाहिए और आपको इस देश में रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे आतंकवाद का समर्थन करने वाली कोलंबिया विश्वविद्यालय की एक छात्रा को स्व-निर्वासन के लिए सीबीपी होम ऐप का इस्तेमाल करते देख खुशी हुई। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने 10 मार्च को सीबीपी होम ऐप पेश किया था, जिस पर स्व-निर्वासन की जानकारी देने की सुविधा वाला फीचर उपलब्ध है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोग देश छोड़ने का इरादा जाहिर करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि सीबीपी ऐप अवैध प्रवासियों को देश छोड़ने और स्व-निर्वासन का विकल्प देता है, ताकि उन्हें भविष्य में कानूनी रूप से अमेरिका लौटने और अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सके। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, उन्हें निर्वासित करेंगे और वे कभी अमेरिका वापस नहीं आ पाएंगे। विभाग के मुताबिक, आईसीई एचएसआई नेवार्क के अधिकारियों ने वेस्ट बैंक की मूल निवासी फलस्तीनी छात्रा लेका कोर्डिया को एफ-1 वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रहने के लिए गिरफ्तार किया है। विभाग के अनुसार, हाजिरी कम होने के कारण लेका का वीजा 26 जनवरी 2022 को रद्द कर दिया गया था। उसने बताया कि लेका को अप्रैल 2024 में न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय परिसर में हमास समर्थक विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछले हफ्ते यहूदी छात्रों के लगातार जारी उत्पीड़न को लेकर विश्वविद्यालय की निष्क्रियता के कारण कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर के संघीय अनुदान और अनुबंधों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की थी।

संघर्ष विराम की उम्मीदों के बीच विनाशकारी हमले

रूस-यूक्रेन ने एक-दूसरे पर दागे सैकड़ों ड्रोन

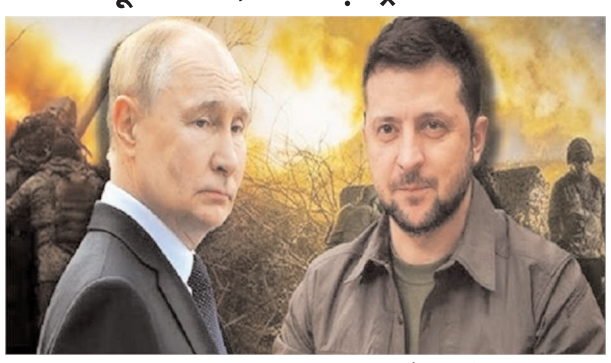

इंटरनेशनल डेस्क: रूस और यूक्रेन ने शनिवार रात को एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किये और दोनों पक्षों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 100 से अधिक दुश्मन के ड्रोन देखे जाने की सूचना दी। यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ से यूक्रेन के साथ युद्ध में 30 दिन के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव के विवरण पर चर्चा करने के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुआ है। वोल्गोग्राद क्षेत्रीय गवर्नर आंद्रेई बोचारोव ने पुष्टि की है कि ड्रोन के गिरते मलबे के कारण शहर के क्रास्नोअर्मेस्की जिले में लुकोइल तेल रिफाइनरी के पास आग लग गई। हालांकि उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दीं। स्थानीय मीडिया के अनुसार, आस-पास के हवाई अड्डों पर उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं। हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। करीब तीन साल पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद से, वोल्गोग्राद रिफाइनरी को कीव की सेनाओं द्वारा कई बार निशाना बनाया गया है, सबसे हाल ही में 15 फरवरी को इसपर ड्रोन से हमला किया गया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने यूक्रेन के 126 ड्रोन को नष्ट कर दिया है, जिनमें से 64 को वोल्गोग्राद क्षेत्र में गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि वोरोनिश, बेलगोरोड, ब्रायंस्क, रोस्तोव और कुर्स्क क्षेत्रों में भी ड्रोन को नष्ट किया गया। इस बीच, यूक्रेन की वायु सेना ने शनिवार को कहा कि रूस ने शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात भर में देश पर 178 ड्रोन हमले किए। उसने बताया कि यह बमबारी शाहिद प्रकार के हमलावर ड्रोन और हवाई सुरक्षा को भ्रमित करने के लिए बनाए गए नकली ड्रोन से किये गए। इनमें से करीब 130 ड्रोन मार गिराए गए, जबकि 38 और ड्रोन अपने लक्ष्य से भटक गए।

नालंदा में बुजुर्ग महिला से दरिंदगी: दुष्कर्म के बाद हत्या, गेहूं के खेत में मिला शव

नालंदा. बिहार के नालंदा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के लंदा गांव में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। महिला शनिवार को चारा लाने खेत गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। जब परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो उनका शव गेहूं के खेत में नग्न अवस्था में मिला।

शव पर मिले संघर्ष के निशान, हत्या से पहले हुआ दुष्कर्म!

परिजनों के अनुसार, मृतका के शरीर पर दांत से काटने के निशान और गले पर दबाव के गहरे घाव थे, जिससे यह साफ होता है कि उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महिला ने हमलावरों से बचने के लिए संघर्ष किया होगा। खेत में उसके पास से हसुली (घास काटने का धारदार औजार) भी मिला है, जिससे लगता है कि उसने हमलावरों का सामना करने की कोशिश की होगी।

जमीन विवाद की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

मृतका के पुत्र ने बताया कि उनकी मां का पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद था। हालांकि, अभी तक किसी के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है।

स्नस्रुऔर डॉग स्क्वायड की मदद से सुराग तलाशने में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। इसके साथ ही एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए नालंदा के एसपी ने खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया, वहीं महिला थाना की अध्यक्ष को भी विशेष जांच का निर्देश दिया गया है।

क्या बिहार में सुरक्षित हैं महिलाएं? बढ़ते अपराधों पर उठे सवाल

बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अब सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर बहस छिड़ गई है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में भय का माहौल बना दिया है।

उन्नाव में मुस्लिम शख्स की मौत पर परिवार का दर्द, कहा- जबड़ा बाहर निकला था...जबरन रंग डाला और मौत तक पीटा

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक मुस्लिम शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। यह घटना कोतवाली सदर थाना क्षेत्र में होली के दिन हुई। मृतक की पहचान शरीफ (55) के रूप में हुई है, जो होली के दिन सामान लेने जा रहे थे और रास्ते में उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शख्स पर जबरन रंग डाला गया और बाद में उसे पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कुछ स्थानीय युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात सामने आई है और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं।

मृतक की बड़ी बेटी ने कहा कि मेरे पिता सामान लेने गए थे, और उन पर जबरन रंग डाल दिया गया। फिर उनकी बुरी तरह पिटाई की गई, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। हमें न्याय चाहिए और जिन लोगों ने यह किया है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मृतक की बड़ी बहन ने भी कहा कि हमारे भाई पर जबरन रंग क्यों डाला गया? वह रोज़ा रख रहे थे और फिर उनकी पिटाई की गई, जो बहुत गलत था। हमारे घर में तीन बेटियां हैं, अब घर का क्या होगा, हमें नहीं पता। सबने मिलकर उन्हें मार डाला।

मृतक के पड़ोसी समीर ने कहा कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह बहुत गलत हुआ है। जब हम उनके रंग में भंग नहीं डालते तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनसे कोई लड़ाई नहीं थी। वह रोज़ा रखकर घर का सामान लेने गए थे, और फिर उनकी हत्या कर दी गई। चश्मदीद गवाह शमीम ने बताया कि मैं सामान लेने गया था और देखा कि कुछ लोग शख्स पर रंग डाल रहे थे। मैंने मना किया और झगड़ा शांत करवा दिया। फिर शख्स ई-रिक्शा में बैठकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां उसकी फिर से पिटाई की गई। रंग डालने वाले लोग उसका पीछा कर रहे थे। चश्मदीद ने बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो शख्स बुरी तरह पीटा हुआ था। उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसे दौड़ाकर बहुत परेशान किया गया था और जबड़ा बाहर निकल आया था। रंग उसके शरीर पर था, और शायद उसे हार्ट अटैक भी आया हो। घटना स्थल पर मृतक को पानी पिलाने वाले रमेश प्रधान ने कहा कि हमने उन्हें पानी पिलाया था और फिर उनके रिश्तेदार उन्हें लेकर चले गए। इसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्नाव में रंग डालने वाले घर की महिला राजकुमारी और मंजू ने कहा कि बचों ने रंग डाला था, लेकिन उन्होंने हत्या नहीं की थी। उनका कहना था कि रंग डालने के बाद शख्स गाली देने लगा और उल्टा-सीधा बोलने लगा। फिर वह ई-रिक्शा में बैठकर आगे बढ़े और वहां जाकर उनकी मौत हो गई।

मामले में पुलिस की जांच जारी

उन्नाव के एडिशनल एसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि मृतक की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। होली के रंग डालने की बात सामने आई है, और हम इस पर जांच कर रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों के आधार पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के पक्ष में बोलने वाले अपने राजदूत का पासपोर्ट किया रद्द

इंटरनेशनल डेस्क: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा भारत के पक्ष में बोलने वाले राजदूत से बदसलूकी का मामला सामने आया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मोरक्को में तैनात अपने राजदूत हारुन अल-रशीद का पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दिया है। हारुन अल-रशीद ने हाल ही में सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करते हुए एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने वालों का खुलासा किया था। उनकी इस पोस्ट के बाद सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना की सरकार को हटाने के बाद अंतरिम सरकार ने 11 दिसंबर 2024 को हारुन अल-रशीद को तत्काल ढाका लौटने और विदेश मंत्रालय में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। लेकिन उन्होंने इस आदेश को नजरअंदाज करते हुए कनाडा का रुख कर लिया।

वहीं से उन्होंने शुक्रवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर सरकार की आलोचना करते हुए पोस्ट साझा की। हारुन अल-रशीद ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश के लिए एक अपील - और मेरे लिए भी। विषय- यूनुस के शासन में बांग्लादेश की अराजकता की ओर बढ़ना और दुनिया की चुप्पी दर्दनाक है। 5 अगस्त 2024 को देश ने एक काला दिन देखा, जब एक योजनाबद्ध आतंकी हमले के जरिए प्रधानमंत्री शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका गया। जब देश संकट में था, तब मुहम्मद यूनुस एक तानाशाह के रूप में उभरे।

राजदूत की इस पोस्ट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भड़क गई और तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। शुक्रवार शाम को विदेश मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए हारुन अल-रशीद और उनके परिवार के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई है। हारुन अल-रशीद ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि बांग्लादेश में मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काने में किन तत्वों की भूमिका रही है। उनकी इस पोस्ट से सरकार की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा, जिससे तानाशाही रवैया अपनाते हुए यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569